Website : www.mantrabharat.com
जुनून है सच लिखने का
E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

मंत्र भारत
हिन्दी दैनिक

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 11
अंक : 36
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
गुरूवार, 12 फरवरी, 2026

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 नवनिर्वाचित महापौर एवं उपमहापौर को ... 4 ड्रैगन की सेना में आई दरार, अपने ही जनरल... 7 टी20 वर्ल्ड कप : सुपर ओवर थ्रिलर में दक्षिण ...

संक्षिप्त न्यूज

सुप्रीम कोर्ट में असम सीएम हिमंत सरमा के खिलाफ एक और याचिका सूचीबद्ध, नफरती भाषण देने का आरोप

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कथित नफरत भरे भाषणों को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के खिलाफ दायर एक और याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है। इससे पहले भी एक अलग याचिका में वायरल वीडियो के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के खिलाफ एक और याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है। चार लोगों ने यह याचिका दायर की है। याचिका में मुख्यमंत्री पर एक समुदाय के लोगों के खिलाफ कथित नफरत भरे भाषण देने का आरोप लगाया है।
मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग याचिका पर सुनवाई करने की बात कही थी। यह याचिका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता एनी राजा ने दायर की थी। इसमें एक वायरल वीडियो का जिक्र है। वीडियो में कथित तौर पर मुख्यमंत्री को एक समुदाय की ओर राइफल से निशाना लगाते और गोली चलाते दिखाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
बुधवार को कोर्ट से कहा गया कि नई याचिका को भी उसी मामले के साथ सूचीबद्ध किया जाए। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा, 'हम देखेंगे।'
किन लोगों ने दायर की याचिका?
नई याचिका पूर्व प्रोफेसर हिरेन गोहेन, असम के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) हरेकृष्ण डेका, वरिष्ठ पत्रकार परेश चंद्र मलाकर और वरिष्ठ वकील शांतनु बोरठाकुर ने दायर की है।

योगी ने हर व्यक्ति को बनाया 'दोगुना अमीर'

महिला-युवा और किसानों के लिए खोला खजाना

नई दिल्ली। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश कर दिया। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत के इस बढ़े बजट में सरकार ने महिलाओं, किसानों, युवाओं और रोजगार निर्माण पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। शिक्षा को 12.4 प्रतिशत और स्वास्थ्य को छः प्रतिशत बजट आवंटित कर योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि उनकी प्राथमिकता स्वस्थ और शिक्षित समाज के निर्माण की है। सरकार ने यह भी बताया है कि उसके कार्यकाल में करीब 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और राज्य की प्रति व्यक्ति आय दो गुनी होकर एक लाख 20 हजार से अधिक हो गई है। किसानों की आय भी दो गुनी हो चुकी है। इस तरह कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल में यूपी वासियों को दो गुना अमीर बना दिया है।
यह भी पढ़ें- लोकसभाः एपस्टीन फाइल्स, ट्रंप की धौंस से लेकर अमेरिका के दबदबे तक... राहुल गांधी ने इन बातों पर सरकार को घेरा

महिलाओं के लिए योगी सरकार की बड़ी घोषणा
महिलाएं योगी आदित्यनाथ की बड़ी समर्थक बनकर उभरी हैं। इसका कारण है कि योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत काम किया है।

बजट के माध्यम से भी योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को मजबूत करने का काम किया है। बजट में अनुसूचित जातियों की गरीब बेटियों के विवाह के लिए 100 करोड़ और सामान्य वर्ग की गरीब बेटियों के विवाह के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। मेधावी छात्राओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।

किसान यूपी की शक्ति, खोला खजाना
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का सबसे बड़ा योगदान है। प्रदेश की बड़ी जनसंख्या आज भी कृषि कार्यों के माध्यम से ही अपना जीवन निर्वाह कर रही है। इसे देखते हुए सरकार ने बजट में किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। गन्ना किसानों को भुगतान में 3000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यूपी अनेक खाद्य फसलों के उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है। सरकार ने इसको बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

युवाओं के लिए रोजगार पर ध्यान
यूपी सरकार की बड़ी सफलता यह है कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर अब केवल 2.26 प्रतिशत रह गई है। योगी सरकार को यह सफलता लगातार औद्योगिक ढांचे के विस्तार, पर्यटन और मूलभूत ढांचे में निवेश के कारण मिली है। सरकार ने भविष्य में भी युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने को ध्यान में रखकर अभी से भविष्योन्मुखी विषयों पर ध्यान केंद्रित करने का काम किया है। डाटा सेंटर बनाने, एक लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा से रोजगार सृजित करने में सफलता मिलेगी। फरवरी 2024 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए हैं। इनसे 10 लाख नए रोजगार के अवसर बनेंगे।
योगी सरकार ने जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 225 करोड़ के साथ-साथ डेटा क्लस्टर सेंटर, टेक्नोलॉजी मिशन बनाने की घोषणा की है, उससे भविष्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। अकेले वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 30 हजार नई नौकरियों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए 3822 करोड़ का बजट रखा गया है। इससे भी रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
सरकार ने बताया है कि प्रदेश में 2.19 लाख नई भर्तियां की गई हैं, जबकि 10 लाख नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। युवाओं को मुफ्त कोचिंग सुविधा सहित शिक्षा का बजट बढ़ाया गया है।

विपक्ष की बड़ी चूक! स्पीकर ओम बिरला को हटाने वाले नोटिस में ही मिलीं खामियां, हो सकता था खारिज

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने की मांग करने वाले विपक्षी सांसदों द्वारा प्रस्तुत नोटिस में खामियां पाई गई हैं। लोकसभा सचिवालय सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि नोटिस में कुछ घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए चार जगहों पर वर्ष 2026 के बजाय 2025 लिखा गया था और इस आधार पर नोटिस को खारिज भी किया जा सकता था। हालांकि, अध्यक्ष ने सचिवालय को नोटिस में मौजूद खामियों को दूर करने और आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ओम बिरला ने नियमों के अनुसार त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया है।

बजट सत्र के दूसरे चरण के प्रारंभ होने के बाद नोटिस को सूचीबद्ध किया जाएगा। संशोधित नोटिस प्राप्त होने के बाद, निर्धारित नियमों के अनुसार इसकी तुरंत जांच की जाएगी। विपक्ष ने बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस मंगलवार को लोकसभा महासचिव को सौंपा और बिरला पर पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन संचालित करने, कांग्रेस सदस्यों पर झूठे इल्जाम लगाने तथा अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।
लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि विपक्षी सांसदों द्वारा मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए दिए गए नोटिस में कमियां पाई गईं। घटनाओं का उल्लेख करते हुए चार बार फरवरी, 2025 लिखा गया हैजिसके आधार पर नियमानुसार नोटिस को खारिज किया जा सकता था। उन्होंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने सचिवालय को निर्देश दिया कि दोषपूर्ण नोटिस में सुधार करवा के इस पर कार्यवाही की जाए।

रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, संसद में बच्चों जैसा व्यवहार करना ठीक नहीं

नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की आत्मकथा को लेकर चल रहे विवाद के बीच जमकर निशाना साधा और उनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को 'राजनीतिक हथियार' के रूप में इस्तेमाल न करने को कहा। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए रिजिजू ने उनसे बच्चों जैसा व्यवहार न करने को कहा। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं राहुल गांधी को सबक नहीं सिखा सकता। मुझे समझ नहीं आता कि वे किस दुनिया में रहते हैं। कौन सी विचारधारा उनके कार्यों को प्रेरित करती है?
रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों को उन्हें समझाना चाहिए कि संसद इस तरह काम नहीं कर सकती। यहां बच्चों जैसा व्यवहार न करें। हमारा देश विशाल है और सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारी सुरक्षा को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना और किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना सही नहीं है।

कटरा रोपवे परियोजना पर विवाद और गहराया, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल पर मंजूरी देने का आरोप लगाया, भाजपा भड़की

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में प्रस्तावित रोपवे परियोजना को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। सोमवार को बजट चर्चा के दौरान शुरू हुआ यह विवाद मंगलवार को भी तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप के साथ जारी रहा।
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने खड़े होकर स्पष्ट किया कि रोपवे परियोजना को उनकी कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कराई गई जांच में यह सामने आया है

कि सितंबर 2024 में इस परियोजना को कैबिनेट ने नहीं, बल्कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वीकृति दी थी।
मुख्यमंत्री के इस बयान पर Bharatiya Janata Party के विधायकों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। एक भाजपा विधायक ने दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि उसमें कैबिनेट की मंजूरी का उल्लेख है और वह कागज विधानसभा अध्यक्ष को भी सौंपा गया। इसके बाद सदन का माहौल और गरमा गया।
इस मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि यह केवल किसी एक क्षेत्र से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से संबंधित विषय है। उन्होंने कुछ विधायकों पर लोगों को गुमराह करने और झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग भी की।
यह विवाद सोमवार को तब शुरू हुआ था, जब बनी के विधायक रामेश्वर ने बजट चर्चा के दौरान रोपवे परियोजना का विरोध करते हुए कहा था कि हिंदू धर्म में यह आस्था है कि श्रद्धालु पैदल चलकर माता के दर्शन के लिए जाते हैं।

मोहाली में हड़कंप! 16 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ नहीं मिला

चण्डीगढ़ **(एजेंसी)**। पंजाब के मोहाली में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शहर के 16 प्रतिष्ठित निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तुरंत स्कूलों को खाली कराया और गहन तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी (ईंध) दर्ज कर ली है। धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए मामले को मोहाली के फेज-7 स्थित साइबर पुलिस थाने को सौंप दिया गया है। तकनीकी टीमें अब आईपी एड्रेस और ईमेल के ओरिजिन की जांच कर रही हैं।
अधिकारियों ने बताया कि गहन जांच के बाद किसी भी स्थान पर कोई संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई। विद्यालय के अधिकारियों ने अभिभावकों को संदेश भेजकर छुट्टी की घोषणा की। उन्होंने बताया कि स्कूल आ रहे छात्रों को वापस घर भेज दिया गया।
मानव मंगल स्कूल, शिवालिक पब्लिक स्कूल और लर्निंग पाथ्स स्कूल उन विद्यालयों में शामिल हैं जिन्हें बम की धमकी वाले ईमेल प्राप्त हुए। पुलिस ने बताया कि विद्यालय के अधिकारियों ने सुबह साढ़े सात बजे से आठ बजे के बीच ईमेल प्राप्त होने की सूचना दी थी जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू की।

अधिकारियों ने बताया कि विद्यालयों द्वारा अलर्ट जारी करने के बाद पुलिस ने शिक्षण संस्थानों की गहनता से जांच की। उन्होंने बताया कि जिन विद्यालयों को धमकी भरे ईमेल मिले हैं, उनमें सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हरमनदीप सिंह हंस ने पत्रकारों से कहा, ''पुलिस अधीक्षकों, पुलिस उपाधीक्षकों और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस टीम को निरीक्षण टीम और बम निरोधक दस्तों के साथ विद्यालयों में भेजा गया।''
उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान में करीब 300 पुलिसकर्मी शामिल रहे और सभी 16 विद्यालयों को खाली करा लिया गया। हंस ने कहा कि फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर और चंडीगढ़ मुख्यालय के आस पास के जिलों से अतिरिक्त बल और विशेष टीम के सहयोग से लगभग ढाई घंटे के भीतर सभी विद्यालयों की जांच पूरी कर ली गई। उन्होंने कहा, ''किसी भी स्थान पर कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली।'' तलाशी अभियान की निगरानी एसपी (पुलिस अधीक्षक) सिटी दिलप्रीत सिंह, एसपी नवनीत सिंह महल, मोहित अग्रवाल, सुखनाज सिंह, रमनदीप सिंह और तलविंदर सिंह गिल; डीएसपी (पुलिस उपाधीक्षक) सिटी-1 पृथ्वी सिंह चहल, डीएसपी सिटी-2 हरसिमरन सिंह बल और सभी थाना प्रभारियों ने की।

एपस्टीन फाइल का जिक्र कर राहुल गांधी ने सरकार पर किया सीधा वार

पीएम मोदी दबाव में हैं'

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को सवाल उठाया कि उद्योगपति अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं हैं। उन्होंने संसद में आरोप लगाया कि एपस्टीन से संबंधित फाइलों में उनका नाम है। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी जिक्र किया और दावा किया कि पुरी जानते हैं कि अनिल अंबानी को एपस्टीन से किसने मिलवाया था।
राहुल गांधी ने कहा कि एक व्यवसायी अनिल अंबानी हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि वह जेल में क्यों नहीं हैं? कारण यह है कि उनका नाम एपस्टीन फाइलों में है। मैं हरदीप पुरी से भी पूछना चाहता हूं कि उन्हें एपस्टीन से किसने मिलवाया था। मैं जानता हूं कि उन्हें किसने मिलवाया था, और हरदीप पुरी भी जानते हैं कि उन्हें किसने मिलवाया था। केंद्रीय बजट पर अपने भाषण के बाद, कांग्रेस नेता ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए अपने आरोपों को दोहराया और दावा किया कि प्रधानमंत्री सीधे दबाव में हैं।
गांधी ने पत्रकारों से कहा कि मैंने कहा है कि मैं आंकड़ों की प्रामाणिकता की पुष्टि करूंगा। न्याय विभाग के पास एपस्टीन

मामलों से संबंधित फाइलें हैं जिनमें हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के नाम हैं। अडानी के खिलाफ चल रहे एक मामले में समन जारी किए गए हैं। भारत सरकार ने पिछले 18 महीनों से कोई जवाब नहीं दिया है। प्रधानमंत्री पर सीधा दबाव है। मुख्य बात यह है कि सामान्य परिस्थितियों में कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेगा। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी प्रधानमंत्री आंकड़ों, किसानों, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा के मामले में ऐसा नहीं करेगा। कोई व्यक्ति ऐसा तभी करेगा जब उस पर कोई दबाव हो।
31 जनवरी को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में जारी एपस्टीन फाइलों के कथित हिस्से के रूप में सामने आए एक ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2017 की इजराइल यात्रा के संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस संदर्भ को एक दोषी अपराधी की बेतुकी बकवास करार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें तथाकथित एपस्टीन फाइलों से संबंधित एक ईमेल संदेश की रिपोर्ट मिली है जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की आधिकारिक इजराइल यात्रा के तथ्य के अलावा, ईमेल में बाकी के संदर्भ एक दोषी अपराधी की बेतुकी बकवास से ज्यादा कुछ नहीं हैं, जिन्हें पूरी तरह से नकार दिया जाना चाहिए।

ईसी ने बंगाल में चुनाव से पहले दिए बड़े फेरबदल के निर्देश, इन अधिकारियों के होंगे तबादले

कोलकाता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों को देखते हुए प्रशासन में बड़े फेरबदल के निर्देश दिए हैं। आयोग ने राज्य सरकार से उन सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का तबादला करने को कहा है, जो पिछले तीन साल या उससे ज्यादा समय से एक ही जिले या पद पर तैनात हैं। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।
इन प्रशासनिक अधिकारियों का होगा फेरबदल?
आयोग के निर्देश के मुताबिक, यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम), ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) और उप-मंडल अधिकारी (एसडीओ) जैसे जिला स्तर के सभी प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू होगा। पुलिस विभाग में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें आईजी (आईजी), डीआईजी (डीआईडी), एसपी (एसपी) और अतिरिक्त जैसे सीनियर पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह कदम स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आयोग का मानना है कि लंबे समय तक एक ही जगह तैनात रहने से चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। प्रशासनिक तटस्थता बनाए रखने के लिए यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसे आयोग हर बड़े चुनाव से पहले अपनाता है।
इन अधिकारियों को मिलेगी राहत
आयोग ने एक और महत्वपूर्ण नियम लागू किया है। जो अधिकारी पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान किसी जिले में जिला मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग ऑफिसर या इंस्पेक्टर के रूप में तैनात थे, उन्हें इस बार उस जिले में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि स्टेट हेडक्वार्टर में तैनात अधिकारियों को ट्रांसफर के निर्देश से छूट मिलेगी।
चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को इन निर्देशों का तुरंत पालन करने के लिए पत्र भेज दिया है।

'अभी तक कोई ऐसा नहीं जन्मा, जो देश बेच सके'; राहुल गांधी के बयान पर वित्त मंत्री की दो टूक

नई दिल्ली। लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर हुई आम चर्चा पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में राहुल गांधी के 'देश बेचने' वाले बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी ऐसे शख्स का जन्म नहीं हुआ, जो देश को बेच सके। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष पर तीखा हमला बोला।
निशाने पर आई टीएमसी
महिला सुरक्षा के विषय पर उन्होंने कहा कि एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री कहती हैं कि महिलाओं को रात में घर से नहीं निकलना चाहिए। ये अपने राज्य की कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे और महिलाओं को दोष दे रहे हैं। कोलकाता में हुए रेप पर एक सांसद ने कहा कि अगर गुनहगार दोस्त ही निकले, तो हम क्या कर सकते हैं? महिला सुरक्षा के विषय में अभिषेक

बनर्जी कह रहे हैं कि हमने कानून बनाया है, गवर्नर को भेजा और वहां से राष्ट्रपति के पास पेंडिंग में है, हम क्या करें? उन्होंने कहा कि बंगाल में बम चलता है, कानून नहीं।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट पर कम्युनिस्ट लोगों ने बयान दिया है कि हमें कुछ नहीं मिलता। कम्युनिस्ट के राज में कानून व्यवस्था इतनी नीचे चली जाती है कि कोई निवेश वहां नहीं पहुंचता। केरल में एक इंडस्ट्री ग्रुप ने करोड़ों का अपना निवेश हटाया और दूसरी जगह चले गए। इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए राज्य मेहनत करते हैं, मगर हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट लोग सरकार में रहते हुए ऐसा कुछ नहीं करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अनुसूचित जातियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध केरल में होते हैं। प्रति एक लाख की आबादी पर 661 अपराध केरल में हो रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ भी सबसे ज्यादा अपराध दर केरल में है। इसमें लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं।
राहुल पर बोला सीधा हमला
राहुल गांधी के बयान पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी तरह-तरह की बातें करते हैं। उन्होंने चेयर पर बैठे जगदम्बिका पाल को अपनी पार्टी का नेता बताया और बिट्टू को देशद्रोही कहा था। ऐसा कहने वाले हमारे विपक्ष के नेता हैं।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने डेटा पर चिंता व्यक्त की कि देश का डेटा विदेश जा रहा है। यह सही नहीं है। हम डेटा सेंटर के लिए प्रावधान कर रहे हैं। हम डेटा भारत में रखने के लिए प्रावधान कर रहे हैं, जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी मिल सके।

देश का पहला 'मुंबई क्लाइमेट वीक' 17-19 फरवरी को मुंबई में विश्वभर के विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज होंगे शामिल

मुंबई(संवाददाता)

जलवायु परिवर्तन के समाधान की दिशा में भारत का पहला मुंबई क्लाइमेट वीक 17 से 19 फरवरी 2026 के बीच मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन ग्लोबल साउथ देशों के लिए जलवायु नेतृत्व का नया मंच तैयार करेगा। तीन दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में वैश्विक स्तर के सरकारी प्रतिनिधि, उद्योग जगत के नेता, जलवायु विशेषज्ञ, संस्थाएँ, युवा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

इस पहल का आयोजन स्वयंसेवी संस्था प्रोजेक्ट मुंबई द्वारा किया जा रहा है, जिसे महाराष्ट्र सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, एमएमआरडीए और बृहन्मुंबई महानगरपालिका का सहयोग प्राप्त है।

कार्यक्रम का मुख्य केंद्र जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में स्थापित होगा, जबकि शहरभर के महाविद्यालयों, सामुदायिक केंद्रों और सांस्कृतिक संस्थानों में 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएँगी। आयोजकों के अनुसार, वास्तविक जलवायु समाधान को प्रदर्शित और विस्तार देने पर विशेष ध्यान रहेगा।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह आयोजन भारत की जलवायु विषयक सक्रिय नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। सरकार, उद्योग, वित्त, विशेषज्ञ और युवाओं को एक मंच पर लाना स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य के प्रति महाराष्ट्र की प्रतिबद्धता का संकेत है।

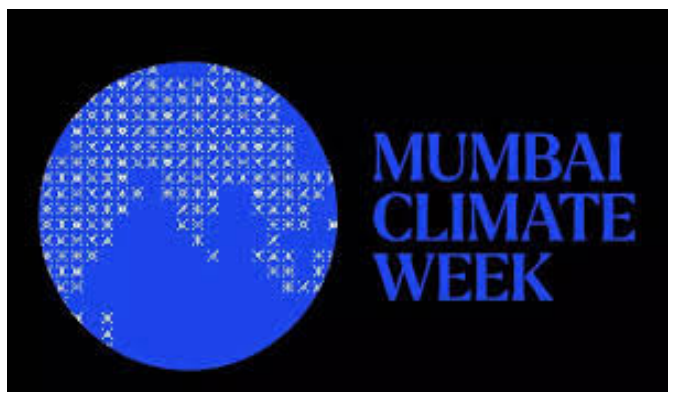

प्रोजेक्ट मुंबई के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर जोशी ने कहा कि यह पहल जलवायु संकट के सामने मुंबई की दृढ़ता और रचनात्मकता को दर्शाती है। इसे भारत का पहला व्यापक नागरिक-आधारित जलवायु आंदोलन बताया गया है।

संवाद, नवाचार और युवा सहभागिता

मुख्य हब में नेतृत्व संवाद, विषयगत परिसंवाद, नवाचार प्रतियोगिता, युवा हरित नवाचार चुनौती और समाधान प्रदर्शनी आयोजित होगी। पहले दिन अर्थशॉट प्राइज की विशेष प्रस्तुति होगी, जिसमें प्रकृति, खाद्य प्रणाली और जनकेंद्रित समाधान पर ध्यान रहेगा।

अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और शुभांशु शुक्ला छात्रों से संवाद कर विज्ञान, अंतरिक्ष और जलवायु जिम्मेदारी के संबंध को समझाएँगे।

कार्यक्रम तीन प्रमुख स्तंभों खाद्य प्रणाली, ऊर्जा संक्रमण और शहरी लचीलापन पर आधारित है। एनएसई के सहयोग से आयोजित नवाचार चुनौती के विजेता नीति-निर्माताओं और निवेशकों के सामने अपने समाधान प्रस्तुत करेंगे।

मुंबई भर में सार्वजनिक व्याख्यान, फिल्म प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नागरिक कार्यशालाओं के माध्यम से जलवायु कार्रवाई को जनसुलभ बनाया जाएगा। प्रदर्शनी क्षेत्र में स्टार्टअप, उद्योग, विश्वविद्यालय और स्वयंसेवी संस्थाएँ व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करेंगी।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रमुख भागीदार है, डेलॉइट रणनीतिक ज्ञान भागीदार है, जबकि टीआईएसएस और आईआईटी मुंबई शैक्षणिक भागीदार हैं। नागरिक मंच के माध्यम से लोग रचनात्मक अभिव्यक्ति कर सकेंगे और यूनिसेफ के YuWaah कार्यक्रम के जरिए युवाओं को नेतृत्व के अवसर मिलेंगे।

30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, सरकार, वित्त, उद्योग, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र के सदस्य इसमें भाग लेंगे।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिलेरी क्लिंटन, बिल गेट्स, राजीव शाह, आईएफसी के इमाद फखुरी, क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर, तथा भारत के वरिष्ठ नेता, उद्योगपति, परोपकारी और पर्यावरण कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

सतर्क टिकट चेकिंग रेल कर्मचारी ने बहादुरी से यात्री की जान बचाई

मध्य रेल के मुंबई मंडल के कमर्शियल क्लर्क कम टिकट कलेक्टर (सीसीटीसी) श्री जॉन पॉल ने असाधारण बहादुरी का परिचय देते हुए एक यात्री की जान बचाई।

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पॉल दिनांक 07.02.2026 को कुर्ला स्टेशन पर ड्यूटी पर थे। दोपहर 12:30 बजे सीएसएमटी जाने वाली एक लोकल ट्रेन कुर्ला स्टेशन पर रुकी और फिर चलने लगी। जैसे ही ट्रेन ने थोड़ी गति पकड़ी, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक बुजुर्ग महिला का पैर फिसल गया और वह प्लेटफार्म पर गिर गईं। यह देखकर श्री पॉल तुरंत मदद के लिए दौड़े और महिला को चलती ट्रेन से खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले आए और यात्री की जान बचाई।

इस प्रक्रिया में उन्हें कंधे में मामूली मोच आ गई। सदमे में डूबी बेबी भास्कर गाइकर को टिकट कलेक्टर कार्यालय में आराम से बैठाया गया, पानी पिलाया गया और परामर्श दिया गया।

उनके एक रिश्तेदार को सूचित किया गया और महिला को सुरक्षित घर भेज दिया गया।

सुश्री बेबी भास्कर भावुक हो गईं और उन्होंने जॉन पॉल और रेलवे प्रशासन को धन्यवाद दिया। जॉन पॉल ने यात्री की जान बचाने में सतर्कता, साहस और सूझबूझ का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है और उन्होंने दूसरों के लिए एक आदर्श स्थापित किया है, जिससे वे एक समर्पित रेलवे कर्मचारी और एक संवेदनशील व्यक्ति होने के अपने कर्तव्य का पालन कर सकें।

मध्य रेल यात्री की जान बचाने में जॉन पॉल के अनुकरणीय शौर्य की सराहना करता है।

विभिन्न सतर्क और बहादुर रेलकर्मी लाखों यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे सातों दिन कार्यरत हैं।

रेलवे अपने यात्रियों से चलती ट्रेनों में चढ़ने या उतरने से बचने की अपील करता है, क्योंकि यह प्राणघातक है।

रेलवे सुरक्षा को मजबूती: भुसावल मंडल में जीवनरक्षक सुरक्षा फेंसिंग पहल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर मध्य रेलवे के भुसावल मंडल ने रेलवे सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंडल क्षेत्र में रेलवे पटरियों के किनारे व्यापक सुरक्षा फेंसिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिससे अनधिकृत ट्रैक पार करने और अतिक्रमण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

इगतपुरी-भुसावल, भुसावल-बडनेरा और भुसावल-खंडवा जैसे संवेदनशील रेल खंडों में यह फेंसिंग रेल संचालन और मानव जीवन दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। इसके साथ ही, संभावित मेन रन ओवर और कैटल रन ओवर स्थलों पर इंजीनियरिंग उपाय अपनाए गए हैं तथा सुरक्षित आवागमन के लिए अंडरपास और रोड अंडर ब्रिज जैसे संरचनात्मक सुधारों के साथ-साथ जागरूकता अभियानों पर भी जोर दिया

का मजबूत नेटवर्क विकसित किया गया है। मंडल द्वारा फुट ओवर ब्रिज, एस्केलेटर, लिफ्ट और परिधि दीवारों जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लोगों को ट्रैक पार करने के खतरों के प्रति सचेत किया जा रहा है। यह पहल इस बात का प्रमाण है कि रेलवे का हित और जनहित एक-दूसरे से जुड़ा है। सुरक्षा फेंसिंग न केवल रेल संचालन को सुरक्षित बनाती है, बल्कि अनगिनत जीवन की रक्षा कर अंत्योदय की भावना को साकार करती है।

मध्य रेल ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अनधिकृत और बिना टिकट यात्रा करने वाले 34.34 लाख यात्रियों से जुर्माने के रूप में 203.76 करोड़ रुपये वसूले

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मुंबई मंडल में बिना टिकट/बिना उचित टिकट यात्रा करने वाले 9.49 लाख उपनगरीय यात्रियों से जुर्माने के रूप में 27.39 करोड़ रुपये वसूले गए

मध्य रेल अपने सम्मानित यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता के तहत, अपने पूरे नेटवर्क में अनधिकृत और बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए अपने उपायों को तेज कर रहा है।

संगठित और व्यवस्थित टिकट जांच अभियानों के माध्यम से, मध्य रेल ने वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से जनवरी 2026) के दौरान महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26

मध्य रेल की समर्पित टिकट जाँच टीमों ने वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से जनवरी 2026) के दौरान बिना टिकट यात्रा कर रहे, गलत या अमान्य यात्रा प्राधिकरण वाले 34.34 लाख यात्रियों को पकड़ा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 31.28 लाख यात्रियों को पकड़ा गया था, जो लगभग 9.8इ की वृद्धि दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से जनवरी 2026) के दौरान जुर्माने के रूप में रिकॉर्ड 203.76 करोड़ रुपये वसूले गए, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 167.61 करोड़ रुपये वसूले गए थे, जो 21इ से अधिक की वृद्धि है। जनवरी 2026 के दौरान, मध्य रेल की टिकट जाँच टीमों ने बिना टिकट यात्रा करने वाले, गलत या अमान्य यात्रा प्राधिकरण वाले 3.58 लाख यात्रियों को पकड़ा, जबकि जनवरी 2025 में यह संख्या 3.27 लाख थी, जो लगभग 9.5इ की वृद्धि दर्शाती है। जनवरी 2026 में अपराधियों से जुर्माने के रूप में 20.60 करोड़ रुपये वसूल किए गए, जबकि जनवरी 2025 में यह राशि 15.62 करोड़ रुपये थी, जो लगभग 32इ की वृद्धि दर्शाती है।

मुंबई मंडल उपनगरीय टिकट जाँच अभियान

उपनगरीय रेलवे मुंबई मंडल की जीवनरेखा है और अनधिकृत यात्रा को रोकने के लिए समय-समय पर विशेष जाँच की जाती है। वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से जनवरी 2026) के दौरान, मुंबई मंडल की टिकट जाँच टीमों ने बिना टिकट/बिना उचित टिकट के यात्रा करने वाले 9.49 लाख उपनगरीय यात्रियों से जुर्माने के रूप में 27.39 करोड़ रुपये वसूल किए। जनवरी माह में 1.14 लाख उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाया गया और जुर्माने के रूप में 3.42 करोड़ रुपये वसूल किए गए।

वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से जनवरी 2026) में बिना टिकट/अवैध टिकट के यात्रा करते पकड़े गए यात्रियों के लिए मंडलवार विवरण और उनसे वसूल की गई जुर्माने की राशि इस प्रकार है:

भुसावल मंडल से 8.18 लाख मामलों में 68.86 करोड़ रुपये, मुंबई मंडल से 14.51 लाख मामलों में 62.73 करोड़ रुपये, पुणे मंडल से 3.84 लाख मामलों में 23.73 करोड़ रुपये, नागपुर मंडल से 3.68 लाख मामलों में 22.91 करोड़ रुपये, सोलापुर मंडल से 2.06 लाख मामलों में 9.46 करोड़ रुपये और मुख्यालय से 2.06 लाख मामलों में 16.06 करोड़ रुपये।

मध्य रेल अनधिकृत यात्रा का पता लगाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाता है, जिसमें स्टेशन चेक, एम्बुश चेक, फोर्ट्रेस चेक, गहन चेक और मेगा टिकट चेकिंग अभियान शामिल हैं। ये अभियान मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों, पैसेंजर ट्रेनों, स्पेशल ट्रेनों और उपनगरीय ट्रेनों में चलाए जाते हैं।

मध्य रेल यात्रियों से अपील करता है कि वे अधिकृत विक्रेताओं द्वारा जारी वैध टिकटों के साथ यात्रा करें, या रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटरों से, या एटीवीएम के माध्यम से, या वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक करें। यात्री अपने मोबाइल फोन पर रेल वन ऐप डाउनलोड करके भी टिकट बुक कर सकते हैं।

मध्य रेल यात्रियों से यह भी अपील करता है कि वे फर्जी टिकट बनाने/प्राप्त करने और उन पर यात्रा करने के लिए धोखाधड़ी के साधनों का उपयोग न करें। यह अपराध भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 के तहत दंडनीय है, जिसमें जुर्माना और 7 वर्ष तक की कैद या दोनों हो सकते हैं।

रेलवे बिना टिकट यात्रा के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता नीति को दोहराता है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यात्रियों को आरामदायक और सम्मानजनक यात्रा अनुभव मिले। सुरक्षित यात्रा करें, जिम्मेदारी से यात्रा करें, गरिमा के साथ यात्रा करें।

विमुक्त जाति एवं घुमंतू जनजाति युवाओं के लिए शिक्षा-रोजगार का समग्र रोडमैप तैयार- अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

मुंबई । विमुक्त जातियों और घुमंतू जनजातियों के युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए वसंतराव नाइक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था (वैनार्टी) का एक समग्र रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए। यह रोडमैप युवाओं को अधिक शिक्षा एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा प्रतिपादन अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण मंत्री ने किया।

वैनार्टी के संचालक मंडल की पहली बैठक मंत्री अतुल सावे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संयुक्त सचिव सुनील तुम्बारे, वैनार्टी के प्रबंध निदेशक प्रशांत वावगे तथा संचालक मंडल के सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

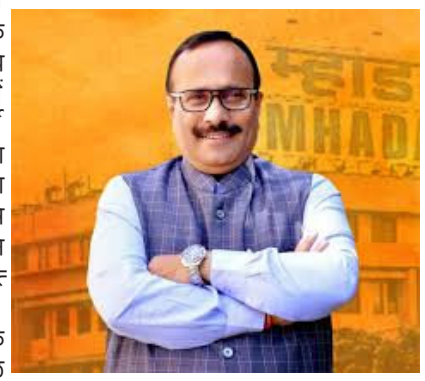

मंत्री अतुल सावे ने बताया कि वैनार्टी के माध्यम से महाज्योति की तर्ज पर यूपीएससी, एमपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दो हजार विद्यार्थियों को पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। साथ ही कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में तीन सौ पचास विद्यार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।

संस्था के कामकाज में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से आंतरिक लेखा परीक्षण नीति, लेखा नीति तथा कर्मचारी भर्ती योजना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने को भी स्वीकृति दी गई, जिससे विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक कौशल प्राप्त हो सकेंगे।

बैठक में संस्था की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी देते हुए चालू वित्तीय वर्ष तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निधि प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ समझौते कर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

पिपलिया-मंदसौर सेक्शन में फाटक क्रमांक 149 दोहरीकरण कार्य हेतु 12 घंटे रहेगा बंद

रतलाम। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के अंतर्गत नीमच-रतलाम दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत पिपलिया-मंदसौर रेलखंड पर आवश्यक इंजीनियरिंग कार्य किया जाना है। इस कार्य के तहत किमी 287/11-13 पर स्थित समपार फाटक क्रमांक 149 को अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नीमच-रतलाम दोहरीकरण कार्य हेतु फाटक दिनांक 12 फरवरी 2026 को शाम 17:00 बजे से 13 फरवरी 2026 को सुबह 05:00 बजे तक के लिए सड़क यातायात हेतु बंद रहेगा, ताकि दोहरीकरण से संबंधित आवश्यक कार्य सुरक्षित एवं सुचारु रूप से किया जा सके।

रेलवे प्रशासन द्वारा सड़क उपयोगकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि उक्त अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा असुविधा से बचने के लिए यात्रा पूर्व उचित योजना बनाएं। यह अस्थायी असुविधा भविष्य में बेहतर रेल परिचालन एवं संरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक है।

मुंबई दौरे के दौरान वीआईपी की यात्रा में कड़े इतजाम हों - प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई । भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रगति में महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी कारण विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति मुंबई का दौरा करते रहते हैं। ऐसे में उनके दौरों के दौरान किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, यह निर्देश राज्य के प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल ने दिए।

फ्रांस के राष्ट्रपति आगामी दिनों में मुंबई का दौरा करने वाले हैं। इसी अवधि में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भी मुंबई दौरा प्रस्तावित है। इन दोनों अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरे की तैयारियों की समीक्षा प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल ने सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित बैठक में की। बैठक में विभागीय सचिव राजेश गावंडे सहित संबंधित सभी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रतिनिधिमंडल के साथ सीधे मुंबई आ रहे हैं, जो महाराष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इस दौरे के दौरान सुरक्षा एवं प्रोटोकॉल में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वीज़ा, इमिग्रेशन, यातायात व्यवस्था, स्वच्छता तथा वाहनों की स्थिति जैसे सभी पहलुओं की गहन समीक्षा कर जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एजेंसियों से आपसी समन्वय और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की अपील की तथा प्रोटोकॉल विभाग के सचिव को समन्वय की जिम्मेदारी निभाने के निर्देश भी दिए।

मध्य रेल

निविदा सूचना

ई-निविदा सूचना क्र.: एलसीएफ/डीआर/एसी/504/2025/23

कार्य का नाम तथा स्थान: "मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन में लंबी दूरी की ट्रेनों के कल्याण पृथक्करण के अंतर्गत कल्याण में विभिन्न सेवा भवनों में वीआरएफ एयर कंडीशनिंग का डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग।" **कार्य की अनुमानित लागत:** ₹2,03,75,867/- (दो करोड़ तीन लाख पचहत्तर हजार आठ सौ सड़सठ रुपये मात्र)। **जमा कराये जाने वाली बयाना राशि:** ₹2,51,900/- (दो लाख इक्यावन हजार नौ सौ रुपये मात्र)। **कार्य पूर्ण करने का अवधि:** स्वीकृति पत्र जारी होने के दिन से 06 (छह) महीना तक (मानसून सहित)। **निविदा पप्रत्र की लागत:** 00 (शून्य)। **ऑफर की वैधता:** निविदा खुलने के 60 दिन तक। **पुरी जानकारी के लिए वैबसाइट, नोटिस बोर्ड का स्थान:** निविदा सूचना और निविदा दस्तावेज़ क्रिस कि वैबसाइट पता ireps.gov.in से देखे जा सकते हैं। निविदा भरने की तारीख तथा समय: निविदा दस्तावेज़ ऑनलाइन दिनांक 05.03.2026 समय 15:00 बजे: तक या पहले भरी जा सकती है। **निविदा खोलने तारीख तथा समय:** निविदा इस कार्यालय मे 15:00 बजे दिनांक 05.03.2026 को खोली जाएगी।

नोट: संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक रुप से उनके प्रस्तावों को निविदा भरने से पहले, नियम और शर्तों, पात्रता मानदंड, ईएमडी और निविदा दस्तावेज की लागत जमा करने के तरीके के संबंध में निविदा विवरण के क्रिस के वेबसाइट ireps.gov.in का संदर्भ लेना चाहिए।

सुरक्षित यात्रा करें, फुड़बोर्ट पर यात्रा न करें 892

मध्य रेल

रुपांतरण कार्य

खुली ई-निविदा संख्या: केवायएन-एलडी-585-डब्लु-758-कांट

कार्य का विवरण: मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के कल्याण-मनमाड सेक्शन पर, कलमगांव में किलोमीटर 98/2 पर हाइड्रोलिक पुल के पास, अतगांव और थानसिट के बीच दो लेन वाली आर यू बी के निर्माण के संबंध में मौजूदा ओएचई में परिवर्तन। **अनुमानित लागत:** ₹59,25,475.78, **ईएमडी:** ₹1,18,500/-, **निविदा पपत्र का शुल्क:** 0.00, **समापन अवधी:** 12 महिने। ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथी एवं अवधि दि. 02.03.2026 को 11:00 बजे है। ई-निविदा की विस्तृत जानकारी रेल की अधिकारीक वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा की जानकारी वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (क. वि) मध्य रेल, कल्याण के सूचना पट पर उपलब्ध है।

सुरक्षित यात्रा करें, फुटबोर्ट पर यात्रा न करें 886

पश्चिम रेलवे-वडोदरा मंडल

फुट ओवर ब्रिज का प्रावधान

निविदा सं.: इएल-टीआरडी-टेंडर-25-26/23R. भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबंधक (कर्षण वितरण) वडोदरा द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिये निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। **क्र. सं. 1 - निविदा सं.: इएल-टीआरडी-टेंडर-25-26/23R, कार्य का नाम:** विश्वमित्री और पालेज में एफओबी (फुट ओवर ब्रिज) की व्यवस्था से संबंधित ओएचई संशोधन कार्य और वड़ोदरा यार्ड और इलेक्ट्रिक लोको शेड में ओएचई कार्य। **कार्य की अनुमानित लागत:** ₹ 1,78,43,714/- **बोली प्रतिभूति:** ₹ 2,39,200/- **निविदा की राशि एवं कार्य समापन की अवधि:** कार्य समापन की अवधी 18 माह, **निविदा की समय सारणी:** निविदा बंद होने का दिनांक एवं समय 11/03/2026 को 15.00 बजे। **वेबसाइट विवरण और सूचना का लोकेशन जहां पूर्ण विवरण देखा जा सकता है तथा कार्यालय का पता विवरण जानकारी के किए:** वेबसाइट विवरण www.ireps.gov.in मंडल रेल प्रबंधक (कर्षण वितरण) पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वड़ोदरा - 390 004

354

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांतदादा पाटिल

मुंबई ।उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। चयन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को प्राप्त अंकों की सूची उनके विस्तृत विवरण सहित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत भर्ती प्रक्रिया की घोषणा करते हुए उसे मंजूरी दी गई है, यह जानकारी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांतदादा पाटिल ने दी।

मंत्री पाटिल ने बताया कि इस निर्णय से घंटेवारी, संविदा और तदर्थ आधार पर कार्यरत सहायक प्राध्यापकों को बड़ी राहत मिलेगी। उनके कार्यकाल के अनुभव को पात्रता निर्धारण में शामिल किया जाएगा, जिससे वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को लाभ मिलेगा। एंथ्रोपोलॉजी शाखा के प्राध्यापकों के लिए पूर्व में लागू स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में प्रकाशन की अनिवार्यता को आंशिक रूप से शिथिल किया गया है। इस शाखा के शिक्षकों के पुस्तक प्रकाशन के अंकों को भी ध्यान में रखा जाएगा तथा समान अवसर के सिद्धांत को अपनाया गया है। साथ ही उत्कृष्टता को प्राथमिकता देते हुए एनआईआरएफ, क्यूएस और टाइम्स हायर एजुकेशन जैसी रैंकिंग के अनुसार अंकों में संशोधन किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को भी अवसर मिलेगा।

सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापक पदों के लिए अनुभव, शोध परियोजनाओं तथा शीर्ष संस्थानों से प्राप्त निधि को महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए साक्षात्कार में मूल्यांकन प्रक्रिया को भी विस्तृत किया गया है। इसमें आईसीटी कौशल, उन्नत तकनीकी दक्षता और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों को महत्व दिया गया है। इस प्रकार शिक्षक चयन प्रक्रिया को पूर्ण करने को मंजूरी दी गई है। संबंधित शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

नवनिर्वाचित महापौर एवं उपमहापौर को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की बधाई

मुंबई के आम नागरिकों के सपनों को साकार करेंगे महापौर, उपमहापौर एवं पदाधिकारी– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई ।भारतीय जनता पार्टी की पार्षद ऋतु तावड़े को बृहन्मुंबई महानगरपालिका का महापौर तथा शिवसेना के संजय घाडी को उपमहापौर चुना गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुष्पगुच्छ देकर दोनों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महापौर, उपमहापौर और सभी पदाधिकारी महानगरपालिका को सही दिशा देंगे तथा मुंबई के आम नागरिकों के सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करेंगे। उन्हें सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा और उनके माध्यम से नए मुंबई के निर्माण को गति मिलेगी।

महापौर और उपमहापौर के निर्वाचन के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका सभागृह में मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे ने मीडिया से बातचीत की। इस अवसर पर मुंबई शहर के सह-पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा, पूर्व सांसद राहुल शेवाले, विधायक अमित साटम, प्रवीण दरेकर, चित्रा वाघ सहित

अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ऋतु तावड़े एक अनुभवी और सशक्त मराठी चेहरा हैं। उन्होंने अब तक मुंबईकरों के मुद्दों पर प्रभावी और आक्रामक भूमिका निभाई है। महायुति सरकार द्वारा शुरू किया गया मुंबई का विकास कार्यक्रम अब उनके नेतृत्व में महानगरपालिका के माध्यम से और बेहतर तरीके से लागू होगा। वहीं उपमहापौर संजय घाडी के अनुभव का भी महानगरपालिका को लाभ मिलेगा। हिंदू हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे की जन्मशताब्दी के अवसर पर जिस प्रकार के प्रशासन की अपेक्षा थी, वह महानगरपालिका के माध्यम से साकार होगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महानगरपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण वहां प्रशासक व्यवस्था थी, लेकिन अब लोकतंत्र की अपेक्षा के अनुरूप जनप्रतिनिधियों का शासन स्थापित हुआ है, जिससे आम नागरिक अपने जनप्रतिनिधियों के और अधिक निकट महसूस करेंगे।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई को एक अत्यंत सक्षम महापौर और उपमहापौर मिले हैं। पिछले कुछ वर्षों में मुंबई के विकास को गति मिली है और मुंबईकरों ने उस विकास को स्वीकार किया है। सरकार का लक्ष्य मुंबई को विश्वस्तरीय शहर बनाना है। झोपड़पट्टी मुक्त, गड्ढा मुक्त और प्रदूषण मुक्त मुंबई के लिए सरकार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई को वित्तीय प्रौद्योगिकी राजधानी बनाने के स्वप्न को भी सरकार साकार करेगी, ऐसा उपमुख्यमंत्री ने कहा।

जो देश में आतंक फैलाए, उससे क्रिकेट क्यों? इंडिया-पाकिस्तान मैच पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

राज्यसभा सांसद और शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और सरकार की पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच खेलने पर चुप्पी पर सवाल उठाया। नई दिल्ली में एएनआई से बात करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि सबसे पहले, चाहे यह पाकिस्तान का यू-टर्न हो या नहीं, मेरा सवाल सिर्फ बीसीसीआई से है। हम पीसीबी और आईसीसी की ओर क्यों देख रहे थे कि मैच होना चाहिए या नहीं? जैसा कि उन्होंने कहा कि हम मैच नहीं खेलेंगे, क्या हमें दो बार यह नहीं कहना चाहिए था कि हम इस आतंकवादी देश के साथ मैच नहीं खेलना चाहते?

इससे पहले सोमवार को, पाकिस्तान सरकार ने अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में मौजूदा चैंपियन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को निर्धारित मैच के लिए मैदान में उतरने का निर्देश दिया था। पाकिस्तान सरकार के एक बयान के अनुसार, यह निर्णय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी द्वारा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीसीबी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के बीच उच्च स्तरीय वार्ता के परिणामों के बारे में जानकारी देने के बाद लिया गया।

उन्होंने पूछा कि मेरा सवाल यह है: हमारी बीसीसीआई, जो सबसे शक्तिशाली, सबसे धनी और सबसे मजबूत संस्था है, चुप क्यों है और मैच होगा या नहीं, इस बारे में फैसला करने के लिए पीसीबी की ओर क्यों देख रही है? आप कह सकते हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ मैच नहीं खेलना चाहते, जो हमारे देश में आतंक फैलाते हैं। पाकिस्तान ने पहले बांग्लादेश के समर्थन में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज टी20 विश्व कप मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया था। बांग्लादेश को आईसीसी द्वारा सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत से बाहर मैच आयोजित करने के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था।

बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को इस टी20 विश्व कप में शामिल किया गया, क्योंकि आईसीसी ने भारत से बाहर अपने सभी मैच खेलने के उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था। यह निर्णय कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाए जाने के बाद लिया गया था। यह कार्रवाई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देशों के बाद की गई थी, जिसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों से संबंधित चिंताएं व्यक्त की गई थीं।

शरद पवार के स्वास्थ्य में सुधार, अगले दो दिनों में अस्पताल से मिल सकती है छुट्टी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और राज्यसभा सांसद शरद पवार (85) की स्थिति अब स्थिर है। सीने में संक्रमण और सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें सोमवार को पुणे के रूबी हॉल क्लीनिक में भर्ती कराया गया था। बुधवार को उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने राहत भरी खबर देते हुए बताया कि उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। अगले दो दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है। उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों ने बुधवार को यह जानकारी दी। राज्यसभा के सदस्य शरद पवार (85) ने सांस लेने में तकलीफ और लगातार खांसी की शिकायत की थी जिसके बाद उन्हें सोमवार दोपहर पुणे जिले के बारामती कस्बे स्थित उनके आवास से रूबी हॉल क्लीनिक लाया गया था।

अस्पताल के चिकित्सक एवं न्यासी डॉ. साइमन ग्रांट ने एक बयान में बताया कि पवार का स्वास्थ्य स्थिर है और इसमें लगातार सुधार हो रहा है। उनकी समग्र नैदानिक ??स्थिति स्थिर और संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने के समय सीने

में जो जकड़न थी, उस परेशानी पर इलाज का अच्छा असर हो रहा है और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति शारीरिक तनाव और थकान के कारण है, खासकर हाल में की गई व्यापक यात्रा एवं लोगों से लगातार मुलाकातों के कारण यह थकान बढ़ गई है।

डॉ. ग्रांट ने कहा, 'चिकित्सा दल उनके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार होने पर अगले दो दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने की योजना बना रहा है।' पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार मुंह के कैंसर के मरीज रहे हैं। उनके भतीजे एवं उपमुख्यमंत्री अजित पवार की 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में मौत हो गयी थी। अजित पवार की पत्नी एवं महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार अपने बेटे पार्थ के साथ सोमवार शाम शरद पवार का हाल-चाल जानने अस्पताल आयी थीं।

अजित पवार विमान दुर्घटना हादसा नहीं साजिश? भतीजे रोहित पवार ने उठाए वीएसआर कंपनी पर सवाल

मुम्बई **(एजेंसी)**। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित ने बुधवार को अपने चाचा अजित पवार के विमान हादसे से जुड़े हालातों पर फिर से संदेह जताया और इसे साजिश बताया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने विमानन कंपनी पर सवाल उठाए। एरो कंपनी के संचालक मनोज पवार का हवाला देते हुए एनसीपी (एसपी) नेता ने संकेत दिया कि विमान हादसा बारामती में कम दृश्यता के कारण नहीं हुआ था।

रोहित पवार ने कहा अजित पवार महाराष्ट्र के एक बड़े राजनीतिक नेता थे। महाराष्ट्र के लोगों को उनके विमान हादसे पर संदेह है। हमने पिछले 13 दिनों में अपने सूत्रों के आधार पर कुछ जानकारी जुटाई है। हम इस मामले को लेकर भावुक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोज पवार एरो कंपनी के संचालक हैं। उन्होंने आगे कहा कि मनोज पवार ने अजित दादा के सहायक कर्मचारियों, महाराष्ट्र विमानन निदेशक और पायलट सहित एक समूह में कहा कि दृश्यता ठीक है। वीएसआर के मालिक विजय कुमार सिंह ने कहा, 'विमान का रखरखाव ठीक था, पायलट अनुभवी थे और दुर्घटना संभवतः दृश्यता की समस्या के कारण हुई।' इस बयान में कुछ गड़बड़ है।

पवार ने मांग की कि जांच एजेंसियां तकनीकी लॉग और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा करें ताकि उड़ान से पहले उन पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों की पहचान की जा सके। उन्होंने आगे कहा कि एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, 'दादा को ले जा रहे विमान से एक अलग तरह की आवाज आ रही थी और वह नीची उड़ान भर रहा था।' जब विमान स्टॉल हुआ, तो स्टॉल मैन्युअल भी हो सकता है, या कोई यांत्रिक खराबी हो सकती है। पायलट या किसी भी व्यक्ति की यही प्रतिक्रिया होती, जैसा कि पायलट पाठक की थी। विमान का रखरखाव प्रतिदिन करना होता है। तकनीकी लॉग पर किसने हस्ताक्षर किए? हम मांग करते हैं कि जांच के दौरान दस्तावेजों की जांच की जाए।

उन्होंने बारामती में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) की कमी को भी उजागर किया और कहा कि 2023 में इसी तरह की विमान दुर्घटना की जांच समय पर की जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि 2023 में मुंबई में हुए विमान हादसे से पता चलता है कि रनवे समतल था। बारामती में आईएलएस (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम) नहीं है; मुंबई में आईएलएस होने के बावजूद भी विमान दुर्घटना हुई। आईएलएस न होने पर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।

उन्होंने कहा कि 2023 के हादसे में भी वीएसआर का विमान इस्तेमाल हुआ था। अगर हमें पहले से (जांच की) जानकारी होती, तो अजित पवार शायद इस हादसे का शिकार नहीं होते। आज भी, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, नेता हों या कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर दिल्ली आए हों, उन्होंने भी वहां वीएसआर के विमान का इस्तेमाल किया था। वीएसआर द्वारा विमानों के रखरखाव का तरीका गलत है। इसी वजह से 2023 में मुंबई में और अजीत दादा के साथ हादसा हुआ। इसलिए, हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आपात स्थिति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कृपया किसी भी वीएसआर विमान का इस्तेमाल न करें।

जनजातीय विकास विभाग और टाटा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्किल्स के बीच समझौता- 240 विद्यार्थियों को विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण

मुंबई । जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता, उद्योग-संगत और आधुनिक तकनीक आधारित कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महाराष्ट्र शासन के Tribal Development Department, Government of Maharashtra Deewj Tata Indian Institute of Skills (टीआईआईएस), मुंबई के बीच मंत्रालय में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अंतर्गत 240 जनजातीय विद्यार्थियों को उन्नत औद्योगिक तकनीक में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

समझौते पर जनजातीय विकास विभाग के सचिव विजय वाघमारे तथा टाटा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्किल्स के मुख्य वित्त अधिकारी मयंक पलन ने हस्ताक्षर किए।

इस पहल के तहत विद्यार्थियों को अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण, व्यावहारिक शिक्षण तथा उद्योग मानकों के अनुरूप कौशल प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद विद्यार्थियों को रोजगार के सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी टाटा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्किल्स द्वारा निभाई जाएगी।

इस अवसर पर सचिव विजय वाघमारे ने कहा कि उन्नत तकनीक में जनजातीय युवाओं को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। यह समझौता केवल कौशल विकास तक सीमित न होकर जनजातीय विद्यार्थियों की भविष्य की रोजगार क्षमता के लिए एक मजबूत और टिकाऊ आधार तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार और उद्योग क्षेत्र की संयुक्त भागीदारी से जनजातीय युवाओं के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी।

समझौते के अंतर्गत जनजातीय विद्यार्थियों के लिए उन्नत एवं भविष्य उन्मुख औद्योगिक क्षेत्रों के सात विशेष पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक वाहन, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, थ्री-डी प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा ईवी बैटरी टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इसके माध्यम से जनजातीय युवाओं को आधुनिक उद्योग क्षेत्र के अनुरूप कौशलयुक्त और रोजगारोन्मुख बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस अवसर पर जनजातीय संशोधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की संयुक्त निदेशक चंचल पाटिल, गृह अधिकारी विजय गुंड, नवीन और पृथ्वी, UNDP के प्रतिनिधि उज्ज्वल पाहुरकर, उदयन मोहापात्रा एवं उनकी टीम तथा टाटा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्किल्स के अधिकारी श्रेयस पटकर और राधेश्याम उपस्थित थे।

इस सहयोगात्मक समझौते की संकल्पना और सुविधा प्रदान करने का कार्य यूएनडीपी परियोजना प्रबंधन इकाई के सहयोग से किया गया।

'वंदे मातरम मुसलमान विरोधी नहीं', सपा नेता अबू आजमी बोले- देश का सम्मान सबको करना चाहिए

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी ने वंदे मातरम के नए दिशा-निर्देशों पर टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि यह गीत मुसलमान विरोधी नहीं है, बल्कि उनकी धार्मिक मजबूरी है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की अपनी आस्था होती है और किसी पर किसी धर्म के अनुसार कुछ करने का दबाव नहीं होना चाहिए।

हम देश का सम्मान करते हैं

अबू आजमी ने कहा वंदे मातरम का मुसलमान विरोध नहीं कर रहा, लेकिन उसकी धार्मिक मजबूरी है। वह अल्लाह के अलावा किसी और की प्रार्थना नहीं कर सकता। जब हम विधानसभा में जाते हैं तो वंदे मातरम गाया जाता है, हम खड़े रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी की अपनी-अपनी आस्था है।

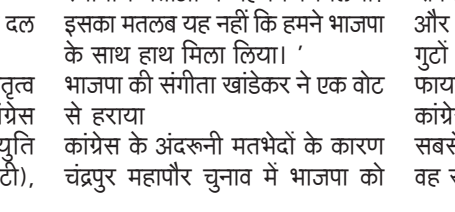

अगर मैं खड़े होकर कुरान की कोई सूरा पढ़ूं और किसी गैर-मुसलमान से पढ़ने के लिए कहूं, तो यह सही नहीं होगा। आपका धर्म जो कहता है आप वह करेंगे, मेरा धर्म मुझे वह करने देता है। हम सब भारतवासी हैं और इस देश का सम्मान करते हैं।

अजित पवार के मामले पर क्या बोलें

अबू आजमी ने भाजपा पर भी टिप्पणी की और कहा कि कभी-कभी कुछ लोग ऐसे मुद्दे लाते हैं, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच विवाद पैदा हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश का संविधान स्पष्ट करता है कि हर नागरिक अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्म का सम्मान करे और मिलकर देश को आगे बढ़ाए। सपा नेता ने दिवंगत अजित पवार के मामले पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को जांच कराने की मांग है, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को इसे स्वीकार करना चाहिए, ताकि मामले में सभी पहलू स्पष्ट हो जाएं।

आरएसएस प्रमुख भागवत के कार्यक्रम में सलमान खान को आमंत्रित करने में गलत क्या है? : शिंदे

मुम्बई **(एजेंसी)**। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संघ प्रमुख मोहन भगवत द्वारा संबोधित एक कार्यक्रम में अभिनेता सलमान खान को आमंत्रित किए जाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का बचाव करते हुए सवाल किया कि आखिर समारोह में फिल्म अभिनेता की उपस्थिति में गलत क्या था। खान समेत कई फिल्मी हस्तियां सप्ताहांत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुईं जिसे भागवत ने संबोधित किया था। मुंबई के नेहरू केंद्र में आयोजित यह कार्यक्रम आरएसएस के शताब्दी समारोह के अंतर्गत आयोजित किया गया था। शिंदे ने कहा कि खान भारतीय नागरिक हैं तथा देश की परंपराओं और संस्कृति में विश्वास रखते हैं। सत्तारूढ़ शिवसेना के प्रमुख शिंदे ने मंगलवार को पूछा, "आरएसएस के कार्यक्रम में सलमान खान को आमंत्रित करने में गलत क्या है?"

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आरएसएस एक देशभक्त संगठन है और देशभक्ति आरएसएस कार्यकर्ताओं के रोम रोम में बसी है। आरएसएस के कार्यक्रम में सलमान खान को भागवत के साथ बातचीत करते देखे जाने के बाद शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में आरएसएस पर कटाक्ष किया था।

राज्यसभा सदस्य ने पूछा था, "क्या यह अभिनेता सलमान खान का स्वागत था या (यह संदेश था कि) संघ और उसकी शाखाओं में मुसलमानों का भी स्वागत है?" हालांकि, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं राज्य के मंत्री नितेश राणे ने मंगलवार को शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए दावा किया कि सलमान खान उनसे "अधिक हिंदू" हैं और आरएसएस प्रमुख के कार्यक्रम में शामिल होने का साहस दिखाने के लिए अभिनेता की प्रशंसा की।

'चंद्रपुर महापौर चुनाव में गड़बड़ी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार', शिवसेना यूबीटी नेता राउत का बयान

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने चंद्रपुर महापौर चुनाव में भाजपा को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस सत्ता नहीं ले सकी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा को समर्थन देने का फैसला स्थानीय स्तर पर हुआ, न कि शीर्ष नेतृत्व की ओर से। पढ़ें रिपोर्ट-

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत ने बुधवार को कहा कि चंद्रपुर के महापौर चुनाव में गड़बड़ी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। शिवसेना (यूबीटी) ने इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था।

राउत ने कहा, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वह चंद्रपुर में सत्ता हासिल नहीं कर पाई। उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी को दोष देने का कोई मतलब है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा, शिवसेना (यूबीटी) के स्थानीय नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्थन किया। यह फैसला स्थानीय स्तर पर हुआ, पार्टी नेतृत्व का फैसला नहीं था।

महाराष्ट्र में किस गठबंधन में कौन दल शामिल हैं?

भाजपा राज्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के साथ महायुति सरकार में है। वहीं, शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) और कांग्रेस विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के घटक हैं।

'स्थानीय नेताओं ने लिया भाजपा से हाथ मिलाने का निर्णय'

राउत ने कहा, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चंद्रपुर के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि भाजपा की मदद न करें, चाहे विपक्ष में बैठना पड़े। फिर भी कांग्रेस की गड़बड़ी के कारण स्थानीय नेताओं ने यह निर्णय लिया। इसका मतलब यह नहीं कि हमने भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। '

भाजपा की संगीता खांडेकर ने एक वोट से हराया

कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों के कारण चंद्रपुर महापौर चुनाव में भाजपा को जीत हासिल करने मौका मिला। भाजपा की संगीता खांडेकर ने कांग्रेस की वैशाली महाडुले को एक वोट से हराया। शिवसेना (यूबीटी) के प्रशांत दानवे को उपमहापौर चुना गया।

कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए: संजय राउत

इस घटना ने विपक्ष की एकता पर सवाल खड़े कर दिए। चंद्रपुर में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और महापौर पद की दावेदार थी। लेकिन विजय वडेट्टीवार और प्रतिभा धनोरकर के नेतृत्व वाले गुटों के बीच मतभेदों का भाजपा ने फायदा उठा लिया। राउत ने कहा कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतिनिधि होने के बावजूद वह सत्ता हासिल नहीं कर पाई।

सम्पादकीय

मतदाता सूची सुधार पर सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश, लोकतंत्र में भरोसा बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी

लोकतंत्र में चुनाव की शुचिता बनाए रखने के लिए मतदाता सूची में समय-समय पर संशोधन जरूरी है। इसी मकसद से देश के विभिन्न राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है। मगर इसमें कई तरह की बाधाएं भी उत्पन्न हो रही हैं। कभी बड़ी संख्या में नागरिकों को मसविदा सूची से बाहर करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो कभी सियासी दलों की ओर से इस प्रक्रिया में नियमों के विपरीत दखल देने के आरोप लग रहे हैं।

ऐसे में सबसे जरूरी है कि नई मतदाता सूची तैयार करने में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता बरती जाए, ताकि सभी पात्र नागरिकों का मताधिकार सुरक्षित रह सके और अपात्र या मृतकों के नाम सूची से हटाने का कार्य बिना किसी विवाद या बाधा के पूरा हो सके। यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल से जुड़े ऐसे ही एक मामले में सोमवार को सभी राज्यों को स्पष्ट कर दिया कि विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद में किसी को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत बिहार से हुई थी और तब से लेकर यह प्रक्रिया विवादों में है। शुरू में चुनाव आयोग की ओर से आधार कार्ड को पहचान पत्र के दस्तावेज में शामिल न करने का मुद्दा प्रमुखता से उठा था। आयोग का तर्क था कि आधार को नागरिकता का पहचान पत्र नहीं माना जा सकता, मगर बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इसे पहचान के दस्तावेज में शामिल कर लिया गया।

अब पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया पर आए दिन नए-नए सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने खुद राज्य में मसविदा सूची में छूट गए मतदाताओं की सुनवाई की प्रक्रिया रोकने का निर्देश दिया था। आयोग ने माना था कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची के डिजिटलीकरण में तकनीकी समस्या की वजह से कई लोगों के नाम मसविदा सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं और ऐसे लोगों के लिए फिलहाल व्यक्तिगत सुनवाई की जरूरत नहीं है।

मगर यह बात भी उतनी ही अहम है कि आयोग की इस कवायद में किसी राज्य सरकार का सीधे तौर पर दबाव या दखल देना उचित नहीं हो सकता।

इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को सफल तरीके से पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं है, बल्कि राज्य सरकारों की भी इसमें अहम भूमिका है। इसके लिए पर्याप्त और सक्षम कर्मी उपलब्ध कराने का जिम्मा राज्य सरकार का होता है। ऐसे में अपेक्षा की जाती है कि इसमें सियासत को दूर रखकर राज्य सरकार और चुनाव आयोग सहयोग एवं समन्वय के साथ काम करेंगे। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में कुछ और कर्मियों को पुनरीक्षण प्रक्रिया में तैनात करने की मांग करता रहा है, जिस पर राज्य सरकार अब जाकर राजी हुई है।

अगर सरकार इस पर पहले ही हामी भर देती, तो इस कार्य में लगे अन्य कर्मियों को भी काम का दबाव नहीं झेलना पड़ता, जिसको लेकर राज्य में सत्तारूढ़ दल की ओर से ही सवाल उठाए जाते रहे हैं। चुनाव आयोग की भी यह प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान के अधिकार से वंचित न हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनी रहे।

वायु प्रदूषण से जुड़ी मौतें, जब स्वास्थ्य का असर दिखता है, लेकिन राष्ट्रीय आंकड़े पीछे रह जाते हैं

बढ़ता वायु प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल बनता जा रहा है। वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग और फसलों के अवशेष जलाना इसके प्रमुख स्रोत हैं, जो फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग और मस्तिष्काघात जैसी जानलेवा बीमारियों का जोखिम बढ़ा देते हैं। यह समस्या न केवल स्वास्थ्य, बल्कि आर्थिक उत्पादकता और कृषि को भी प्रभावित कर रही है। मगर सवाल यह है कि भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों को दर्ज करने के लिए क्या मृत्यु प्रमाणपत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख होना जरूरी है और यदि ऐसा है, तो इसके लिए माकूल व्यवस्था का अभाव क्यों है? यह प्रश्न इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार का कहना है कि देश में ऐसा कोई राष्ट्र-स्तरीय डेटा उपलब्ध नहीं है, जो बीमारियों या मौतों को वायु प्रदूषण से सीधे तौर पर जोड़ता हो।

किसी भी महामारी से निपटने के विज्ञान में 'एक्सपोजर-रिस्पॉन्स मॉडल', अतिरिक्त मृत्यु दर का अनुमान और जनसंख्या-स्तरीय जोखिम आकलन जैसे तरीकों का उपयोग किया जाता है। भारत स्वयं तंबाकू-संबंधी कैंसर और व्यावसायिक जोखिमों से जुड़ी बीमारियों के आकलन में इन तरीकों को स्वीकार करता है। यदि वायु प्रदूषण कोई वायरस होता, तो संभवतः भारत अब तक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर चुका होता। पिछले वर्ष सरकार की ओर से राज्यसभा में दिए गए एक लिखित उत्तर में कहा गया था कि देश में ऐसा कोई निर्णायक राष्ट्र-स्तरीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, जो मौतों या बीमारियों को केवल वायु प्रदूषण से सीधे तौर पर जोड़ता हो।

वर्ष 2007 में भी सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में विश्व स्वास्थ्य संगठन और आईजीआईडीआर के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया था कि घर के भीतर वायु प्रदूषण के कारण लगभग 4.07 लाख भारतीयों की समय से पहले मौत हो गई थी, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा था कि इन मौतों और वायु प्रदूषण के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक डेटा उपलब्ध नहीं है।

इस संदर्भ में यह कहना गलत नहीं होगा कि देशव्यापी मृत्यु प्रमाणपत्रों के अभाव को तकनीकी रूप से सही ठहराया जा सकता है, लेकिन यह चिकित्सकीय सत्य को पूरी तरह नहीं दर्शाता। सार्वजनिक स्वास्थ्य में जिम्मेदारी केवल एक कारण वाले मृत्यु प्रमाणपत्रों से नहीं मापी जा सकती। अधिकांश प्रदूषण-जनित मौतें हृदय और श्वसन संबंधी रोगों के बढ़ने के कारण होती हैं, जहां वायु प्रदूषण एक जोखिम कारक के रूप में काम करता है, न कि अकेले कारण के रूप में। सरकार का तर्क संभवतः तकनीकी पहलू पर आधारित है - अर्थात सार्वजनिक स्वास्थ्य रिकार्ड या ऐसे गहन अध्ययनों का अभाव, जिनमें प्रत्येक मौत को स्पष्ट रूप से 'वायु प्रदूषण-जनित' के रूप में दर्ज किया गया हो।

यह कहना कि 'निर्णायक राष्ट्रीय डेटा' उपलब्ध नहीं है, कुछ हद तक तकनीकी रूप से सही हो सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वायु प्रदूषण मौतों का कारण नहीं बन रहा।

उत्तर भारत के शहरों, विशेषकर दिल्ली में, वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव अब किसी से छिपा नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय और अनेक अध्ययनों ने बार-बार यह दिखाया है कि सूक्ष्म कणों से होने वाला वायु प्रदूषण मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव डालता है। लांसेट पत्रिका में प्रकाशित 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी' के अनुसार, भारत में वर्ष 2019 में दस लाख से अधिक मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुईं, जो देश में कुल मौतों का लगभग 18 प्रतिशत है।

अध्ययन से यह भी पता चला कि वर्ष 1990 से 2019 के बीच सूक्ष्म कणों से होने वाली मृत्यु दर में 115 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि घरेलू वायु प्रदूषण से होने वाली मृत्यु दर में कमी आई। चिंताजनक तथ्य यह है कि वायु प्रदूषण से होने वाला नुकसान बच्चे के जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के एक विश्लेषण से पता चलता है कि विषाक्त वायु भ्रूण में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के प्रवाह को बाधित करती है, जिससे समय से पहले जन्म, नवजात का कम वजन, फेफड़ों के विकास में रुकावट और बाल्यावस्था में दीर्घकालिक श्वसन समस्याओं की आशंका बढ़ जाती है।

पिछले कुछ दशकों में औद्योगिकीकरण, वाहनों की संख्या में तेजी और कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण पर्यावरण को इस कदर नुकसान पहुंचा है कि इसके विषैले तत्व अब हर सांस और भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। नीति-प्रतिक्रियाएं अधिकांशतः अल्पकालिक रही हैं, जबकि यह स्वास्थ्य संकट दीर्घकालिक और अंतर-पीढ़ीगत प्रभाव डालता है।

हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में दिल्ली के छह प्रमुख सरकारी अस्पतालों के रिकार्ड का हवाला देते हुए बताया गया कि पिछले तीन वर्षों में इन अस्पतालों में दो लाख से अधिक गंभीर श्वसन रोगों के मामले दर्ज किए गए, जिन्हें वायु प्रदूषण से जोड़ा गया। बच्चों, बुजुर्गों और अन्य संवेदनशील समूहों में अस्थमा, सांस फूलने और श्वसन संबंधी समस्याओं के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि यह दर्शाती है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव केवल सांख्यिकीय अनुमान नहीं, बल्कि रोजमर्रा की चिकित्सकीय वास्तविकता बन चुका है।

विभिन्न शोध यह भी संकेत देते हैं कि वायु प्रदूषण केवल श्वसन रोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोगजनकों के प्रसार को भी प्रभावित कर सकता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में दिल्ली के कुछ घनी आबादी वाले इलाकों की हवा में एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी जीवाणुओं की मौजूदगी पाई गई। इससे संकेत मिलता है कि सूक्ष्म कण (पीएम 2.5 और पीएम 10) जीवाणुओं के लिए वाहक की तरह काम कर सकते हैं, जिससे वे हवा में लंबे समय तक बने रहते हैं और मानव शरीर तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है।

यह एक ऐसा पहलू है, जो वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य नीति को अब भी अलग-अलग खांचों में देखने की प्रवृत्ति को उजागर करता है। स्वास्थ्य आपातकाल को केवल डेटा की श्रेणियों पर तकनीकी बहस तक सीमित नहीं किया जा सकता। अस्पतालों में हर दिन वायु प्रदूषण के गंभीर प्रभाव देखे जा रहे हैं, लेकिन इन्हें आधिकारिक रूप से स्वास्थ्य संकट नहीं माना जाता, क्योंकि इस तरह की मौतें 'वायु प्रदूषण-जनित' की स्पष्ट श्रेणी में दर्ज नहीं होतीं।

यह चक्रीय तर्क डेटा अंतराल के माध्यम से जवाबदेही में देरी करता है। लाखों भारतीयों के लिए यह संकट रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है - बच्चे और युवा सर्दियों की धुंध भरी हवा में सांस लेने के लिए संघर्ष करते हैं, बुजुर्ग मरीजों से अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है और श्रमिक वर्ग विषाक्त हवा में बिना पर्याप्त सुरक्षा के काम करने को मजबूर है।

ऐसे में भारत को वायु प्रदूषण को केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का एक संरचनात्मक निर्धारक मानना चाहिए। राष्ट्रीय निगरानी प्रणालियों में वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकीकृत करने, आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने और नीति विमर्श में प्रदूषण-जनित मृत्यु दर को स्पष्ट मान्यता देने की आवश्यकता है। ये केवल तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी हैं, जो स्वच्छ हवा में सांस लेने के नागरिक अधिकार से जुड़ी हुई हैं।

लोकतंत्र बनाम प्रपंच की राजनीति : प्रधानमंत्री की आवाज़ से भय क्यों?

प्रोफ़ेसर डॉ दयानंद तिवारी
प्रवक्ता भाजपा,
मुंबई, महाराष्ट्र

भारतीय संसद केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है; यह 'जनता की संप्रभु इच्छा' का जीवंत प्रतीक है। संविधान की प्रस्तावना में 'हम भारत के लोग' लिखकर जो संकल्प लिया गया था, वही संसद में साकार होता है। परंतु जब वही संसद शोर, अवरोध और राजनीतिक आवेग का मंच बन जाए, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है – क्या विपक्ष लोकतंत्र की आत्मा को समझ रहा है या केवल उसका उपयोग कर रहा है?

हाल की घटनाओं में जिस पुस्तक को आधार बनाकर राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने संसद में उग्र हंगामा किया, प्रधानमंत्री को बोलने से रोकने की कोशिश की, कार्यवाही ठप की – बाद में स्पष्ट हुआ कि वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई थी। यदि तथ्य अपुष्ट थे, तो क्या यह आचरण लोकतांत्रिक जिम्मेदारी कहलाएगा? क्या संसद अब अफवाहों की प्रयोगशाला बनेगी?

भारतीय परंपरा कहती है –
'सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्।'
परंतु यहाँ तो स्थिति उलट दिखी – सत्य की प्रतीक्षा किए बिना आरोपों की वर्षा।

प्रधानमंत्री को बोलने से रोकना – जनादेश का अपमान

प्रधानमंत्री किसी दल का प्रवक्ता नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का निर्वाचित प्रतिनिधि है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब प्रधानमंत्री सदन में उत्तर देने खड़े होते हैं और उन्हें शोर से रोका जाता है, तो यह केवल सरकार को नहीं, बल्कि संविधान की उस व्यवस्था को चुनौती है जिसमें उत्तरदायित्व और संवाद अनिवार्य हैं।

लोकतंत्र का अर्थ है – प्रश्न पूछना और उत्तर सुनना। यदि विपक्ष केवल प्रश्न पूछना चाहता है पर उत्तर सुनने को तैयार नहीं, तो यह संवाद नहीं, एकतरफा आरोप संस्कृति है।

राहुल गांधी की राजनीति : आवेग बनाम उत्तरदायित्व

राहुल गांधी की राजनीति बार-बार अधूरी सूचनाओं पर आधारित आक्रोश की राजनीति प्रतीत होती है। संसद जैसे गंभीर मंच पर यदि तथ्य की पुष्टि से पहले तूफ़ान खड़ा कर दिया जाए, तो वह राजनीतिक अपरिपक्वता का संकेत है। नेतृत्व केवल विरोध करने से सिद्ध नहीं होता; नेतृत्व उत्तरदायित्व से सिद्ध होता है।

गीता में कहा गया है –
'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।'
ज्ञान से बढ़कर कुछ पवित्र नहीं। परंतु जब ज्ञान की जगह आवेग ले लेता है, तो राजनीति दिशा खो देती है।

यदि जिस मुद्दे पर सदन ठप किया गया, वह तथ्यात्मक रूप से अपूर्ण निकला, तो क्या कोई नैतिक जवाबदेही तय होगी? क्या लोकतंत्र में क्षमा माँगना भी राजनीतिक कमजोरी मान लिया गया है?

अविश्वास प्रस्ताव : लोकतांत्रिक अधिकार या राजनीतिक प्रदर्शन?

अविश्वास प्रस्ताव संसदीय अधिकार है। परंतु जब संख्या बल स्पष्ट रूप से विपक्ष के पक्ष में न हो और प्रस्ताव केवल प्रतीकात्मक टकराव का माध्यम बने, तो उसकी गंभीरता घट जाती है। यदि बहस चाहिए, तो बहस होने दीजिए। यदि उत्तर चाहिए, तो उत्तर सुनिए। लेकिन यदि उद्देश्य प्रधानमंत्री की आवाज़ को दबाना है, तो यह लोकतंत्र पर अविश्वास है।

संसद ठप – आर्थिक और नैतिक क्षति

संसद का प्रत्येक बाधित घंटा जनता के धन से चलता है। बजट पर चर्चा बाधित होना, विधेयकों का लंबित रहना, नीति निर्माण का विलंब – यह केवल प्रक्रियात्मक समस्या नहीं, विकास पर सीधा आघात है। किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग – सबके मुद्दे शोर में दब जाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह संदेश जाता है कि भारत की राजनीति में संवाद से अधिक टकराव है। जबकि वास्तविकता यह है कि भारत आज वैश्विक मंच पर स्थिर और निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक बन चुका है।

वैश्विक मंच पर सम्मानित नेतृत्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 की सफल अध्यक्षता से लेकर वैश्विक कूटनीति में सक्रिय भूमिका तक भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया है। विश्व भारत को सुन रहा है। विकासशील देशों की आवाज़ बनकर भारत एक नई धुरी के रूप में उभरा है। यह सम्मान स्थिर नेतृत्व और स्पष्ट दृष्टि से प्राप्त हुआ है।

ऐसे समय में घरेलू स्तर पर प्रधानमंत्री की आवाज़ को रोकना केवल राजनीतिक विरोध नहीं, राष्ट्र की सामूहिक छवि पर प्रश्नचिह्न लगाने जैसा है।

लोकतंत्र शास्त्रार्थ से चलता है, शोर से नहीं

भारतीय बौद्धिक परंपरा में शास्त्रार्थ की संस्कृति रही है – तर्क, प्रतितर्क और संवाद। संसद उसी परंपरा का आधुनिक स्वरूप है। यदि विपक्ष इसे केवल प्रदर्शन का मंच बना देगा, तो वह स्वयं अपनी विश्वसनीयता खो देगा।

शोर को समझें नीति, यही उनकी पहचान,
तथ्य जहाँ हों कठोर, वहाँ आरोपों की तान।
संसद को समझें रंगमंच, लोकतंत्र को खेल,
जनादेश की गूंज से फिर भी रहते मेल।
अंततः लोकतंत्र में असहमति अनिवार्य है, परंतु मर्यादा उससे भी अधिक अनिवार्य है। प्रधानमंत्री को बोलने से रोकना, अपुष्ट तथ्यों पर संसद ठप करना, और फिर स्वयं को लोकतंत्र का प्रहरी घोषित करना – यह विरोधाभास अधिक दिन तक नहीं चलेगा।

भारत आज विश्व मंच पर सम्मानित है। इतिहास यह दर्ज करेगा कि इस निर्णायक कालखंड में किसने संवाद को चुना और किसने शोर को। लोकतंत्र अविश्वास से नहीं, उत्तरदायित्व, संयम और विवेक से चलता है।

'विवेकः राष्ट्रस्य प्राणः।'
जब विवेक बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा।

ड्रैगन की सेना में आई दरार, अपने ही जनरल बन रहे खतरा, अपनी सत्ता बचाने की जंग लड़ रहे जिनपिंग

मार्च 2023 में जब चीन की सेना का शीर्ष नेतृत्व राष्ट्र के सामने एकजुट खड़ा दिखाया गया, तब संदेश साफ था कि शी जिनपिंग ने लगभग एक दशक की सत्ता के बाद अपनी पसंद का सैन्य ढांचा खड़ा कर लिया है। अपने भरोसे के अधिकारियों को ऊपर बैठाकर उन्होंने जन मुक्ति सेना को विश्व स्तर की शक्ति बनाने का लक्ष्य रखा था। पर अब वही ढांचा भीतर से हिलता दिख रहा है।

हम आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के नाम पर चल रही कार्रवाई ने सेना के सबसे ऊंचे हलकों को झकझोर दिया है। केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य एक एक कर हटाए जा रहे हैं या जांच के घेरे में आ रहे हैं। ताजा और सबसे चौंकाने वाला मामला शी जिनपिंग के करीबी माने जाने वाले शीर्ष सेनापति झांग योउश्या का है। उनके साथ एक और प्रमुख कमान संभालने वाले अधिकारी लियू झेनली भी पद से हटाए गए हैं।

साल 2023 की शुरुआत में चीन के पास कम से कम तीस ऐसे जनरल और एडमिरल स्तर के अधिकारी थे जो विशेष विभागों और क्षेत्रीय कमानों का संचालन कर रहे थे। अब इनमें से लगभग सभी या तो बाहर कर दिए गए हैं या सार्वजनिक जीवन से गायब हैं। उनकी जगह लगाए गए कई नए अधिकारी भी ज्यादा समय तक नहीं टिके। सक्रिय भूमिका में बचे अधिकारियों की संख्या बेहद कम बताई जा रही है।

शी जिनपिंग की इस कार्रवाई से सेना में नेतृत्व का खालीपन पैदा हुआ है। झांग योउश्या और लियू झेनली जैसे अधिकारी युद्ध की तैयारी और संचालन की योजना में अहम माने जाते थे। उनके अचानक हटने से जन मुक्ति सेना की तैयारी और भरोसे पर असर पड़ना स्वाभाविक है।

केंद्रीय सैन्य आयोग में अब जो प्रमुख चेहरा बचा है वह झांग शेंगमिन हैं, जिनकी पहचान राजनीतिक अनुशासन और भ्रष्टाचार विरोधी जांच से जुड़ी रही है। उन्होंने प्रक्षेपास्त्र बल में लंबा समय अनुशासन अधिकारी के रूप में बिताया। यही बल चीन के परमाणु और पारंपरिक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम संभालता है। पिछले वर्ष उन्हें आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था।

हम आपको यह भी बता दें कि कार्रवाई केवल थल सेना तक सीमित नहीं रही है। नौसेना, प्रक्षेपास्त्र बल और लगभग सभी शाखाओं में यह कार्रवाई चली है। साथ ही पांचों क्षेत्रीय कमान, जिन्हें 2016 में नई संरचना के तहत बनाया गया था, भी इससे अछूती नहीं रहीं। पूर्वी क्षेत्रीय कमान, जो ताइवान के आसपास की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, वहां भी बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं और हाल में नया कमांडर लगाया गया है।

इस बीच, सैन्य अखबार ने अधिकारियों और जवानों से अपील की है कि वे फैसलों का समर्थन करें और शी जिनपिंग के साथ खड़े रहें। साथ ही यह भी माना गया कि इन कदमों से अल्प अवधि की कठिनाई और पीड़ा हो रही है मगर दावा किया गया है कि अंत में सेना और मजबूत बनकर उभरेगी।

इसी बीच रक्षा क्षेत्र से जुड़े तीन सांसदों को भी उनके पद से हटा दिया गया है। ये लोग रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष उड़ान और परमाणु उद्योग से जुड़े थे। इनमें एक बड़ी सरकारी विमान निर्माण कंपनी के पूर्व प्रमुख, एक लंबे समय से परमाणु हथियार अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक और एक सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी के मुख्य अभियंता शामिल हैं। कारण सार्वजनिक नहीं किए गए, पर यह कदम संसद के वार्षिक अधिवेशन से ठीक पहले उठाया गया।

चीन ने 2035 तक पूर्ण सैन्य आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा है। पर सेना के भीतर भ्रष्टाचार को इस राह में बाधा माना जा रहा है। कुछ हटाए गए अधिकारियों के नाम उनकी संस्थाओं की सूची से भी गायब कर दिए गए हैं। साथ ही कई रक्षा कंपनियों में भ्रष्टाचार विरोधी बैठकें तेज कर दी गई हैं।

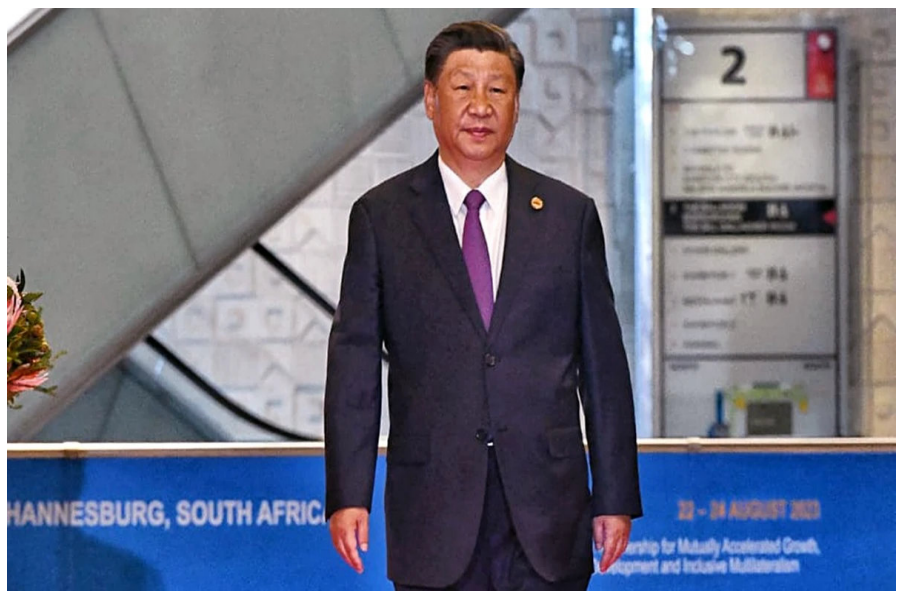

वहीं सबसे गंभीर आरोप यह है कि शीर्ष सेनापति झांग योउश्या पर परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी अमेरिका तक पहुंचाने और रिश्वत लेकर पदोन्नति कराने के आरोप लगे हैं। हालांकि आधिकारिक बयान में उन पर केवल अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन की बात कही गई, पर अंदरूनी ब्रीफिंग में जासूसी और रिश्वत के आरोप चर्चा में रहे। इन घटनाओं के बीच शी जिनपिंग 2027 से आगे भी पार्टी प्रमुख के रूप में बने रहने की राह देख रहे हैं और माना जा रहा है कि उन्हें चौथा कार्यकाल मिल जाएगा। पर उससे पहले उन्हें नए भरोसेमंद सैन्य चेहरे खोजने होंगे।

देखा जाये तो जो कुछ चीन की सेना में चल रहा है वह केवल भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नहीं, बल्कि सत्ता की लोहे की मुट्ठी कसने की कहानी है। शी जिनपिंग ने पहले अपने वफादारों को ऊपर बिठाया, अब वही वफादार भी शक के घेरे में हैं। संदेश साफ है: वफादारी स्थायी नहीं, केवल शी के प्रति पूर्ण समर्पण ही सुरक्षा कवच है।

इसका सामरिक असर भी गहरा है। सेना किसी भी देश की ताकत का आधार होती है। जब शीर्ष कमान बार बार बदले, जब अधिकारियों को हर समय डर रहे कि अगली बारी उनकी है, तब साहसी और स्पष्ट निर्णय लेना कठिन हो जाता है। युद्ध की तैयारी भरोसे, निरंतरता और स्पष्ट आदेश श्रृंखला पर टिकती है। वहां यदि भय और संदेह घर कर जाए तो कागज पर मजबूत दिखने वाली सेना मैदान में डगमगा सकती है।

परमाणु और प्रक्षेपास्त्र बल में उठापटक खास चिंता की बात है। यह वही क्षेत्र है जो प्रतिरोध की अंतिम दीवार माना जाता है। यदि यहां राजनीतिक निष्ठा को पेशेवर दक्षता पर तरजीह दी गई तो गलत आकलन का खतरा बढ़ेगा। दुनिया के लिए यह अस्थिरता का संकेत है।

ताइवान के संदर्भ में भी यह बदलाव मायने रखते हैं। एक तरफ चीन दबाव बनाए रखना चाहता है, दूसरी तरफ उसकी कमान संरचना भीतर से हिल रही है। यह स्थिति या तो उसे जल्दबाजी में कदम उठाने को उकसा सकती है ताकि अंदरूनी कमजोरी छिपे, या फिर उसे कुछ समय के लिए सतर्क बना सकती है। दोनों ही हालात क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित करते हैं।

साथ ही शी जिनपिंग के इरादे समझना कठिन नहीं। वह सेना को केवल राष्ट्रीय रक्षा का साधन नहीं, बल्कि अपनी सत्ता की ढाल और तलवार दोनों बनाना चाहते हैं। उन्हें ऐसी सेना चाहिए जो पहले पार्टी के प्रति, फिर देश के प्रति जवाबदेह हो, और अंत में पेशेवर मानकों की बात करे। वह 2035 का लक्ष्य और 2027 के बाद की अपनी कुर्सी, दोनों सुरक्षित करना चाहते हैं।

पर इतिहास बताता है कि डर पर खड़ी व्यवस्था भले बाहर से कठोर दिखे, पर भीतर से वह खोखली हो सकती है। लगातार सफाई अभियान से कुछ समय के लिए नियंत्रण बढ़ता है, पर साथ ही पहल करने की भावना मरती है। हर अधिकारी जोखिम लेने से बचेगा, हर निर्णय ऊपर की ओर धकेला जाएगा। युद्ध और कूटनीति दोनों में यह कमजोरी बन सकती है। इसलिए चीन की यह अंदरूनी उथलपुथल केवल उसका घरेलू मामला नहीं। यह एशिया की सुरक्षा, वैश्विक शक्ति संतुलन और परमाणु स्थिरता से जुड़ा सवाल है। शी जिनपिंग अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, पर जितनी कसकर मुट्ठी बंद होगी, उतना ही खतरा है कि रेत फिसल भी सकती है।

जनपद स्तरीय 'राष्ट्रीय आविष्कार अभियान' प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में यूपीएस मोहद्दीनपुर की नैंसी, धनपुर ब्लॉक ने मारी बजी

डायट प्राचार्य राजेन्द्र प्रताप, बीएसए अनिल कुमार ने बच्चों को किया प्रोत्साहित

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। बेसिक शिक्षा विभाग, प्रयागराज की ओर से आज 'राष्ट्रीय आविष्कार अभियान' के अंतर्गत जनपद स्तरीय विज्ञान क्विज एवं विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन डायट प्रयागराज में हुआ कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक क्षमता, नवाचार भावना एवं रचनात्मकता का विकास करना है।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उप निदेशक/प्राचार्य डायट राजेन्द्र प्रताप तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अनिल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। डायट प्राचार्य राजेन्द्र प्रताप ने कहा कि 'राष्ट्रीय आविष्कार अभियान बच्चों में 'क्यों, कैसे और क्या' की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करता है। यही जिज्ञासा भविष्य के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नवप्रवर्तकों की नींव तैयार करती है।'

प्रतियोगिता में जनपद के सभी ब्लाकों से चयनित मेधावी छात्र - छात्राएं शामिल हुए। विद्यार्थियों ने एआई रोबोट, स्मार्ट सिटी मॉडल, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, कचरा प्रबंधन तथा सतत विकास जैसे विषयों पर अभिनव एवं उपयोगी मॉडल प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, प्रस्तुतीकरण कौशल एवं वैज्ञानिक समझ ने उपस्थित जनसमूह एवं निर्णायक मंडल को अत्यंत प्रभावित किया। कड़े मुकाबले के बाद विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में प्रथम स्थान यूपीएस मोहद्दीनपुर की नैंसी, द्वितीय स्थान यूपीएस घोघापुर के सुफियान अहमद, तृतीय स्थान

सीएस मेजा की शिवानी, चतुर्थ स्थान बेरुई बहरिया के सूर्य प्रकाश, पंचम स्थान केजीबीवी गोहरी सोराव अनामिका यादव, छठवां यूपीएस खेक्सा के अर्पित पटेल, सातवां स्थान यूपीएस भनोरी के रोहन, आठवां स्थान सीएस नीबी अंशुमान, नौवा सीएस किशुनपुर नीरज, दशम स्थान पर सीएस बरौना के शिवम ने प्राप्त किया।

विज्ञान क्विज प्रतियोगिता में छात्रों ने विज्ञान, गणित एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी बौद्धिक क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कड़े मुकाबले के बाद धनपुर ब्लॉक ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। प्रतिभागियों ने प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जमीनी समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत किए, जिन्हें निर्णायक मंडल द्वारा विशेष रूप से सराहा गया।

प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट, शैक्षिक बैग, पुस्तकें एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। विजेताओं के उत्साहवर्धन हेतु भविष्य में राज्य स्तरीय भ्रमण, जैसे इसरो अथवा अन्य प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों के शैक्षिक भ्रमण पर भेजने की योजना भी साझा की गई।

बीएसए अनिल कुमार ने कहा कि 'ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं और उन्हें नई तकनीकों एवं शोध की दिशा में प्रेरित करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि परिषदीय विद्यालयों के बच्चे भी आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएं।'

कार्यक्रम के संचालन में जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) अभिनव सिंह का विशेष योगदान रहा। परीक्षा नोडल विपिन कुमार, अन्तरिक्ष शुक्ला, शत्रुंजय शर्मा एवं अनुराग पाण्डेय ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों एवं आयोजकों को बधाई देते हुए यह विश्वास व्यक्त किया गया कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के माध्यम से जनपद प्रयागराज के विद्यार्थी विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे।

पत्नी के लापता होने पर आभूषण व्यापारी ने दर्ज कराई गुमशुदगी

थरवई। थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर उर्फ गारापुर गांव निवासी एक आभूषण व्यापारी की पत्नी संदिग्ध परिस्थितियों में घर से दो दिन पहले लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी सुराग न मिलने पर पति ने बुधवार को थाने में तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।जानकारी के अनुसार, पुरुषोत्तमपुर उर्फ गारापुर निवासी रामकुमार सोनी की पत्नी ममता सोनी (30) वर्ष दो दिन पूर्व घर से निकली लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटीं। परिजनों ने रिश्तेदारों व संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद बुधवार को रामकुमार सोनी ने थरवई थाने में तहरीर देकर पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है बताया गया है कि रामकुमार सोनी की शादी वर्ष 2020 में हुई थी। दंपती के दो छोटे बच्चे हैं। रामकुमार सोनी क्षेत्र में आभूषण का व्यवसाय करते हैं। थरवई पुलिस का कहना है कीपीड़ित की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर लिया गया है।

प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी

'नए भारत' के 'नए उत्तर प्रदेश' की मजबूत नींव रखेगा 2026-27 का ऐतिहासिक बजट : नन्दी

पिछले 8 वर्षों में दोगुनी से भी अधिक 30 लाख करोड़ के पार पहुंची प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया 2026-27 का बजट प्रदेश के चौमुखी विकास को तीव्र गति प्रदान करने वाला बजट है। ?9.12 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट 25 करोड़ प्रदेशवासियों के सपनों को हकीकत में बदलने का एक 'रोडमैप' है। 2026-2027 का यह बजट 'नए भारत' के 'नए उत्तर प्रदेश' की मजबूत नींव रखेगा।

मंत्री नन्दी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पिछले 8 वर्षों में दोगुनी से भी अधिक होकर ?30 लाख करोड़ के पार पहुंच गई है। यह प्रदेश में हो रहे सतत निवेश और विकास को दर्शाता है।

यह बजट विकसित भारत 2047 की दिशा में एक ठोस प्रभावी और दूरदर्शी कदम है। 25 करोड़ प्रदेशवासियों की खुशहाली, समृद्धि और जीवन स्तर में सुधार की गारंटी है। मंत्री नन्दी ने कहा कि इस बजट से प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। युवा, महिला, किसान, व्यापारी, उद्यमी सभी की आकांक्षाओं और उम्मीदों को इस बजट के माध्यम से वास्तविकता का आकार मिलेगा। इस बहुआयामी एवं बहुलक्षी बजट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का हार्दिक आभार।

घर पर जबरन कब्जे का आरोप, न्याय की गुहार

प्रयागराज। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के छोटा बघाड़ा इलाके में एक मकान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पीड़ित परिवार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि कुछ दिन पूर्व उनके मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और अब उस पर अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। परिवार का कहना है कि संबंधित मकान वर्ष 1975 से नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज है तथा समय-समय पर हाउस टैक्स का भुगतान भी किया जाता रहा है। परिवार ने एक अधिवक्ता पर कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैनामा कराने और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उनका यह भी कहना है कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। साथ ही परिवार के एक सदस्य के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाने और अन्य मामलों में फंसाने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया। पीड़ितों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।

पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं को साइबर जागरूकता अभियान तहत पम्पलेट वितरित कर जागरूक किया

मंत्र भारत संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक महाजन द्वारा महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान' के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक कुशल पर्यवेक्षण व विश्वजीत सौरयान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक हरें कृष्ण उपाध्याय उसका बाजार के नेतृत्व में थाना उसका बाजार मिशन शक्ति टीम उप निरीक्षक संत कुमार

महिला कांस्टेबल माला मौर्या द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम परसा सुकुरल्लाह में जन चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं को बाल विवाह मुक्त भारत, बहू बेटी सम्मेलन व साइबर जागरूकता अभियान तहत पम्पलेट वितरित कर जगरुक किया गया तथा उनकी समस्याओं को सुना गया, उचित परामर्श के साथ काउन्सलिंग किया गया । बहू-बेटी सम्मेलन लगाकर जागरूक किया गया तथा खुद के साथ होने वाले अपराध से बचने के बारे मे जानकारी दी गयी तथा मिशन शक्ति 5.0 स्टीकर भी चस्पा किया गया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र जहां पर अपनी समस्या को दर्ज करा सकती हैं के बारे में जानकारी दी गई तथा मिशन शक्ति फेज-5.0 के विषय में महिलाओं को महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड केयर लाइन, 108 एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर नए कानून के बारे में जानकारी दी गई व नई धाराओं को भी बताया गया।

मेले के तैयारियों की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष महामण्डलेश्वर पार्वती नंद गिरि, सचिव पायलनंद गिरि को

त्र्यंबकेश्वर कुंभ में भव्यता के साथ होगे शामिलः डा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामण्डलेश्वर प्रो (डा) स्वामी लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी महाराज के नेतृत्व में त्र्यंबकेश्वर (नासिक) कुंभ - 2027 की तैयारियां किन्नर अखाड़ा ने व्यापक स्तर पर शुरू हो गयी है। माघ मेला प्रयागराज और दिल्ली में किन्नर अखाड़ा की हुई बैठक में तय किया गया है कि किन्नर अखाडा के सभी संत, महात्मा, पदाधिकारी और बडी संख्या में शिष्य त्र्यंबकेश्वर (नासिक) कुंभ में शामिल होगे और भव्यता के साथ देवत्व यात्रा और अमृत स्नान किया जाएगा। किन्नर अखाडा की ओर से कुंभ की सभी तैयारियों की जिम्मेदारी महाराष्ट्र की किन्नर अखाडा की प्रदेश अध्यक्ष महामण्डलेश्वर स्वामी पार्वती नंद गिरि और सचिव महामण्डलेश्वर स्वामी पायलनंद गिरि को सौपी गयी है। किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामण्डलेश्वर प्रो (डा) स्वामी लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी महाराज ने

बताया कि त्र्यंबकेश्वर (नासिक कुंभ मेला- 2027,) 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर जुलाई 2028 तक (मुख्य आयोजन 2027 में) गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इसे औपचारिक रूप से घोषित किया है, जिसमें 2 अगस्त 2027 (अमृत स्नान) प्रमुख है। यह कुंभ आधुनिक तकनीक और एआई से युक्त होगा। किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामण्डलेश्वर प्रो (डा) स्वामी लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी महाराज ने बताया कि पहला अमृत स्नान (सोमवती अमावस्या) का स्नान 2 अगस्त 2027, दूसरा अमृत स्नान 31 अगस्त 2027 और तीसरा शाही स्नान 11 सितंबर 2027 (एकादशी) को होगा। उन्होंने त्र्यंबकेश्वर कुंभ की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 12 वर्षों में आयोजित होने वाला यह मेला, 'प्रौद्योगिकी सक्षम कुंभ' होगा, जिसमें एआई के माध्यम से भीड़ प्रबंधन और डिजिटल अनुभव प्रदान किया जाएगा जिसकी व्यापक स्तर पर सरकार तैयारियां कर रही है।

उन्होंने बताया कि यह सनातन धर्म (हिंदुओं) का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश के समय आयोजित होता है। अमृत स्नान (शाही स्नान) के दिन साधु - संत और लाखों श्रद्धालु गोदावरी नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाते हुए अक्षय पुण्य प्राप्त करते हैं।

बैठक में किन्नर अखाडा के संरक्षक महंत दुर्गा दास महराज, महाराष्ट्र की प्रदेश अध्यक्ष महामण्डलेश्वर स्वामी पार्वती नंद गिरि, सचिव महामण्डलेश्वर स्वामी पायलनंद गिरि, पुणे की नायक रंजीता, पिंकी माई श्रीरामपुर, मनीषा माई, काजल माई पुणे सहित अन्य प्रमुख लोग थे।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर परमार्थ निकेतन से भावभीनी श्रद्धाजंलि

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। परमार्थ निकेतन से आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुये भावभीनी श्रद्धाजंलि अर्पित की। उन्होंने अपने जीवन को मूल्यों, नैतिकता और मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश की आत्मा और संस्कृति के सशक्त स्तंभ थे। उनका जीवन, उनके विचार और उनके सिद्धांत आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा, दिशा और आदर्श का स्रोत हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का व्यक्तित्व सादगी, दृढ़ता और समाज सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने जीवन भर यह संदेश दिया कि राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी अर्थव्यवस्था या सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के चरित्र, मूल्यों और नैतिक चेतना में है। उन्होंने हमेशा यह माना कि समाज और राष्ट्र तभी सशक्त बन सकते हैं जब उसके प्रत्येक सदस्य में सदाचार, आत्मनिर्भरता और देशभक्ति का संचार हो।

उनके विचारों का केंद्र एकात्म मानववाद था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस दर्शन के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि समाज का हर व्यक्ति, चाहे गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, वह राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकता है। उन्होंने हमेशा यह कहा कि असली विकास केवल भौतिक समृद्धि तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान में निहित है। उनका यह दृष्टिकोण आज भी देश के नीति-निर्माण, सामाजिक सेवा और युवा नेतृत्व के लिए मार्गदर्शक है। आज जब देश विभिन्न सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार और सिद्धांत और भी प्रासंगिक हो गए हैं। उनका संदेश यह है कि सशक्त समाज का निर्माण केवल सरकारी नीतियों पर निर्भर नहीं, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, नैतिकता और मूल्य आधारित जीवन पर भी निर्भर है। उनका जीवन और कार्य हमें यह प्रेरणा देते है कि हम सभी अपने कर्तव्यों, अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार हों और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। परमार्थ निकेतन से उनकी देशभक्ति को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।

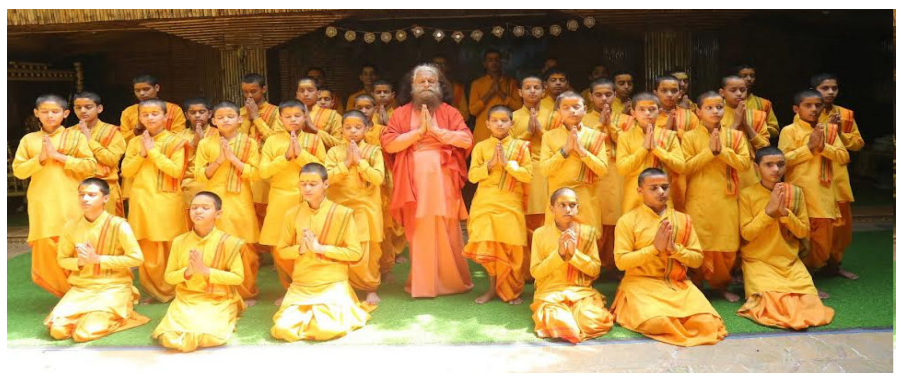

जेटी जुबिली स्कूल में अनुभवात्मक शिक्षण विषय पर दो दिवसीय सामान्य क्षमता संवर्धन कार्यक्रम संपन्न

शिक्षण एक सतत एवं आजीवन चलने वाली प्रक्रिया : सुष्मिता कानूनगो

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। जगत तारन गोल्डेन जुबिली स्कूल, प्रयागराज में अनुभवात्मक शिक्षण विषय पर दो दिवसीय सामान्य क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। यह कार्यक्रम सीबीएसई द्वारा सुझाए गए नवाचारपूर्ण एवं विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षताओं को सुदृढ़ करना तथा कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी, रोचक एवं अर्थपूर्ण बनाने हेतु व्यावहारिक शिक्षण रणनीतियों से उन्हें सुसज्जित करना था। कार्यक्रम में दो विषय विशेषज्ञों डॉ. जेपीएन मिश्र पूर्व प्रोफेसर एवं डीन, केंद्रीय विवि, गुजरात, जो अनुभवात्मक शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं, ने करके सीखने की अवधारणा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अनुभवात्मक शिक्षण विद्यार्थियों में सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, जिससे विषयवस्तु की गहरी समझ विकसित होती है तथा ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग संभव होता है। दूसरे सत्र में डॉ. अनूप कुमार, प्राचार्य, श्रीराम कॉन्वेंट स्कूल, वाराणसी, जो एक प्रख्यात शिक्षाविद् हैं, ने ट्रिपल एच समन्वय–हेड (मस्तिष्क), हार्ट (हृदय) और हैंड (हाथ)–के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी के तीनों क्षेत्रों–संज्ञानात्मक (ज्ञान), भावात्मक (मूल्य एवं दृष्टिकोण) तथा मनो-क्रियात्मक (कौशल)–पर आधारित पाठ योजना निर्माण के तरीकों पर शिक्षकों को मार्गदर्शन दिया, जिससे विद्यार्थियों में स्पष्ट अवधारणा निर्माण सुनिश्चित हो सके।

विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती सुष्मिता कानूनगो के प्रेरणादायक विचारों ने और भी समृद्ध बनाया। उन्होंने कहा कि शिक्षण एक सतत एवं आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षकों को अपनी दक्षताओं का निरंतर उन्नयन करते रहना चाहिए ताकि वे भावी पीढ़ी को सशक्त बना सकें।

ज्वाला देवी के विक्रम बहादुर सिंह को सीएम शिक्षक सम्मान, शिक्षको, विद्या भारती परिवार में हर्ष, दी बधाई

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की गौरवमयी शैक्षणिक परंपरा में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। प्रयागराज के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, सिविल लाइंस के प्रधानाचार्य विक्रम बहादुर सिंह परिहार को प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री अध्यापक सम्मान के लिए चुना गया है। इस घोषणा से प्रयागराज जनपद सहित विद्या भारती काशी प्रांत और पूर्वी उप्र के शिक्षा जगत में उत्साह और गौरव का वातावरण व्याप्त है।

यह सम्मान परिहार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए वर्षों के अथक परिश्रम, नवाचारों और एक अनुशासित शैक्षिक वातावरण तैयार करने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिफल है। उन्होंने न केवल विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को ऊँचा उठाया, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा को संस्कारों और आधुनिक कौशल से जोड़ने का भगीरथ कार्य किया है।

मध्य प्रदेश के सतना जिले के गौनहारी गाँव के निवासी विक्रम बहादुर सिंह परिहार का जीवन सादगी, कर्तव्यनिष्ठा और सैन्य अनुशासन का मेल है। उनके पिता, नरेंद्र प्रताप सिंह परिहार वायु सेना से सेवानिवृत्त होने के पश्चात वर्तमान में कृषि के माध्यम से समाज सेवा में संलग्न हैं। सैन्य पृष्ठभूमि वाले परिवार से होने के कारण परिहार की कार्यशैली में स्पष्ट निर्णय क्षमता और कठोर अनुशासन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शैक्षणिक योग्यता एमकाम, एल एलबी और बीएड है। परिहार की शैक्षिक यात्रा वर्ष 2007 में विद्या भारती योजना के अंतर्गत शक्ति नगर, सोनभद्र में वाणिज्य प्रवक्ता (सीबीएसई) के से प्रारंभ हुई थी। 2017में ज्वाला देवी गंगापुरी में प्रधानाचार्य, 2022 मे सरस्वती विद्या मंदिर, सुलतानपुर (सीबीएसई) में प्रधानाचार्य थे। वर्तमान में ज्वाला देवी सिविल लाइंस, प्रयागराज जैसे प्रमुख संस्थान का कुशलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, उनके मार्गदर्शन में सेवा बस्ती' क्षेत्रों में विशेष संस्कार केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और नैतिक मूल्य प्रदान किए जा रहे हैं, जो राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे पूर्व भी उन्हें उनकी मेधा के लिए उपमुख्यमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान, विभिन्न मंचों पर 'श्रेष्ठ प्रधानाचार्य सम्मान' और अनेक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों द्वारा विशिष्ट सम्मानों से नवाजा जा चुका है। विद्या भारती काशी प्रांत के पदाधिकारियों ने कहा कि यह सम्मान केवल व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि उन आदर्शों का सम्मान है जिन्हें विद्या भारती आत्मसात करती है। यह गौरवपूर्ण उपलब्धि भविष्य मां प्रदेश के हजारों शिक्षकों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगी।

11.35 करोड़ की निधी से शुरू है मरम्मत कार्य, दो वर्ष बाद भी नहीं पूरा हुआ काम

स्व मीनाताई ठाकरे हॉल की मरम्मत हेतु दो वर्ष बाद मिला फंड,कार्य में तेजी आने की संभावना बढ़ी

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

- 1988 में डेढ़ करोड़ में हुआ नाट्यगृह का निर्माण,खस्ताहाल होने के कारण 9 वर्षो से बंद
- राज्य सरकार पर लगा उदासीनता का आरोप ,नाट्य प्रेमियों में फैली नाराजगी

भिवंडी। भिवंडी के मंडई इलाके में स्थित स्व. मिनाताई ठाकरे हाल राज्य सरकार की अनदेखी का शिकार बना हुआ है। ठेकेदार को सरकार द्वारा फंड मुहैय्या कराने में की गई लेटलतीफी के कारण उक्त हॉल का मरम्मत कार्य दो साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है।हालांकि राज्य सरकार द्वारा फिलहाल हॉल की मरम्मत के लिए फंड मुहैय्या करा दिया गया है।जिसके बाद कार्य में तेजी आने की संभावना बढ़ गई है।इधर आयुक्त ने ठेकेदार को 10 दिन में कार्य पूरा न करने पर ठेका रद्द करने की सख्त चेतावनी चेतावनी दी है।जिसके बाद हॉल के मरम्मत कार्य में तेजी आने की संभावना बढ़ गई है।

भिवंडी मनपा ने सन 1988 में लगभग डेढ़ करोड़ रूपये खर्च करके अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न स्व.मीनाताई ठाकरे नाट्यगृह का निर्माण कराया था।लेकिन मनपा प्रशासन की अनदेखी व लापरवाही के कारण उक्त नाट्यगृह बदतर हालात में पहुंचने के कारण जनवरी 2017 से यानी पिछले 9 वर्षों से बंद है। हॉल की रिपेयरिंग की मांग स्थानीय लोगों द्वारा किए जाने के बाद तत्कालीन पालकमंत्री व मौजूद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्व मिनाताई ठाकरे हॉल की मरम्मत के लिए 15 करोड़ की निधी मंजूर की थी। इसके बाद मनपा प्रशासन ने हॉल की मरम्मत करने का 15 करोड़ का निविदा निकाला।जिसे मुंबई की महादेव इंटरप्राइजेस ने 11.35 करोड़ में लिया है।जिसे हॉल की मरम्मत करने का वर्क ऑर्डर 22 फरवरी 2023 को दिया गया।जिसके तहत एक वर्ष में यानी मार्च 2024 तक रिपेयरिंग का काम पूरा करने का ठेकेदार को लक्ष्य दिया गया है।जिसमे हॉल में सिविल वर्क के साथ स्लैब रिपेयरिंग, स्टेज,सीलिंग, लाइटिंग,साउंड, ए सी,कलर आदि काम करना था।लेकिन ठेका देने के दो वर्ष बाद भी काम पूरा नहीं हो सका है।

10 दिन में काम पूरा करने आयुक्त का आदेश

हॉल रिपेयरिंग कार्य का देखरेख कर रहे मनपा के इंजीनियर विनोद मते ने बताया कि हॉल की मरम्मत हेतु सरकार की तरफ से अभी निधी मुहैय्या कराई गई है।जिसके बाद आयुक्त अनमोल सागर ने मंगलवार को हॉल का दौरा कर 10 दिन के अंदर काम पूरा करने का आदेश ठेकेदार को दिया है।आयुक्त ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार का ठेका रद्द कर दिया जाएगा।

बता दे कि ठेकेदार द्वारा बेहद धीमी गति से कार्य किए जाने के कारण अभी तक मात्र 25 फीसदी काम पूरा हो सका है।ठेकेदार का कहना है कि मनपा प्रशासन द्वारा फंड मुहैय्या कराए जाने के बाद कार्य में तेजी लाया जाएगा और निर्धारित समय में कार्य पूरा करने की कोशिश की जाएगी।

कलाकारों को हो रही तकलीफ,फैली नाराजगी

इधर भिवंडी शिवसेना(उद्धव) शहर प्रमुख मनोज पाटील(प्रसाद भाई) ने राज्य सरकार पर जानबूझ कर हॉल के रिपेयरिंग हेतु फंड देने में उदासीनता का आरोप लगाया है।उन्होंने कहा है कि निधी की कमी से तमाम शिवसैनिकों के श्रद्धास्थान मानी जाने वाला मीनाताई ठाकरे रंगायतन बंद पडा है।जिसके कारण शहर सहित ग्रामीण भाग के नाट्य प्रेमियों में मायूसी है तथा भिवंडी के नागरिकों में बडे पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाधा निर्माण हो रहा है।इसी प्रकार नाट्यगृह के अभाव के कारण यहां के नव कलाकारों के कला गुण को भी प्रतिसाद नहीं मिल रहा है इसलिए नव कलाकारों की बड़ पैमाने पर सांस्कृतिक बाधा निर्माण हुई है।इसी प्रकार नाटक का प्रयोग नहीं होने के कारण यहां के नाट्य प्रेमियों को नाटक व अन्य मनोरंजन कार्यक्रम देखने को नहीं मिल रहा है।जिस कारण कल्याण , ठाणे, मुंबई क्षेत्रों में जाना पडता है।

पड़ोसी विवाद पहुंचा पुलिस तक, उत्पीड़न और बदनाम करने की साज़िश का आरोप

सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने का दावा, परिवार की सुरक्षा की मांग

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी के धामणकर नाका क्षेत्र में फ्लैट विवाद ने अब पुलिस उपायुक्त का दरवाजा खटखटा दिया है। स्थानीय निवासी अशरफ रियाज सैयद ने अपने पड़ोसी बाबर नियाज सिद्दीकी के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और बदनाम करने की साज़िश का आरोप लगाते हुए पुलिस उपायुक्त, परिमंडल-2 भिवंडी को लिखित शिकायत दी है। मामले के सामने आने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार वह पिछले दस वर्षों से संबंधित पते पर अपने स्वामित्व वाले फ्लैट में रह रहे हैं। आरोप है कि पड़ोसी द्वारा लगातार घर खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस दौरान गाली-गलौज, विवाद खड़ा करना और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने जैसे कृत्य किए गए हैं, जिससे परिवार मानसिक तनाव में है।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि विरोधी पक्ष द्वारा सोशल मीडिया और एक युटूबर चैनल के माध्यम से उनके खिलाफ कथित रूप से झूठी खबरें प्रसारित कर छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही अज्ञात लोगों को भेजकर डराने-धमकाने तथा पार्किंग क्षेत्र में अनावश्यक रूप से बैठकर मानसिक दबाव बनाने का आरोप भी लगाया गया है। आवेदक ने आशंका जताई है कि उन्हें और उनके परिवार को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिकायत प्राप्त हो चुकी है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उद्घाटन के दिन ही नवनिर्मित होटल में आग लगी, महिला सहित तीन झुलसे

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के मथुरा जिले में वृन्दावन स्थित नवनिर्मित एक होटल में बुधवार को उद्घाटन के दिन ही आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर एक महिला व दो बच्चे झुलस गये। ये तीनों होटल मालिक के परिवार के सदस्य हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि राया नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल ने रुक्मिणी विहार में एक नया होटल बनाया है।

उन्होंने बताया कि आज ही होटल का उद्घाटन किया गया था, और कुछ घंटे बाद ही जब होटल मालिक के परिजन वहां घूम रहे थे, तभी अचानक आग लग गई।

अरबपति शिवम की गिरफ्तारी के लिए प्रदेश पुलिस की दो टीमें दिल्ली रवाना

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के कानपुर में लैंबॉर्गिनी से छह लोगों को कुचलने के मामले में आरोपी शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कापुर लाया जाएगा। शिवम मिश्रा के अधिवक्ता ने दावा किया है कि घटना के समय शिवम कार नहीं चला रहा था, जबकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयान व अन्य सबूतों से यह स्पष्ट है कि गाड़ी शिवम ही चला रहा था। ड्रावर मोहन के सरेंडर को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया था। कार रिलीज के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने कहा कि अभी गड़ी को नहीं छोड़ा जाएगा क्यों उसका टेक्निकल मुआयना करना है।

आप को बता दें कि कानपुर में लैंबॉर्गिनी से छह लोगों को कुचलने के मामले में आरोपी शिवम के वकील मृत्युंजय कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि गाड़ी शिवम के परिवार का चालक मोहन चला रहा था, न कि शिवम। कानपुर के पॉश ग्वालटोली इलाके में 'वीआईपी रोड' पर अपराह्न करीब सवा तीन बजे 10 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की कार लैंबॉर्गिनी ने कई वाहनों को टक्कर मारते हुए कई लोगों को कुचल दिया था। इस घटना में कम से कम छह लोग घायल हो गए थे।

अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने कहा, 'कार परिवार का चालक चला रहा था, न कि शिवम मिश्रा। हम अदालत के समक्ष तथ्य और साक्ष्य पेश करेंगे।' उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि इस मामले को उनके मुवक्किल के खिलाफ सीधे आपराधिक कृत्य के बजाय एक दुर्घटना के रूप में देखा जाए। हालांकि, कानपुर पुलिस ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि अब तक की जांच में यह पुष्टि हो चुकी है कि हादसे के समय कार शिवम मिश्रा ही चला रहा था।

एमबीबीएस परीक्षा में प्रथम शेट्टी की शानदार सफलता, खुशी का माहौल

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

शहर के भाजपा गुटनेता संतोष शेट्टी के सुपुत्र प्रथम शेट्टी ने चिकित्सा क्षेत्र की प्रतिष्ठित एमबीबीएस परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर परिवार के साथ-साथ भिवंडी शहर का नाम रोशन किया है। डी. वाय. पाटिल विश्वविद्यालय से मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रथम को हाल ही में नवी मुंबई स्थित विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित एक भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. शिवानी पाटिल तथा स्कूल ऑफ मेडिसिन के डीन डॉ. राजीव राव के शुभहस्ते प्रथम शेट्टी का सत्कार किया गया। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षकों, विद्यार्थियों और गणमान्य अतिथियों ने उनकी उपलब्धि की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। परिवार के अनुसार, प्रथम ने पढ़ाई के दौरान निरंतर मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ अध्ययन किया। बचपन से ही उनका रुझान चिकित्सा क्षेत्र की ओर था और डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने का उनका सपना अब साकार होने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। प्रथम की सफलता के बाद शहर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। शहर के कई सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्र के मान्यवरों ने भाजपा गुटनेता संतोष शेट्टी तथा पूर्व नगरसेविका शशिलता शेट्टी को बधाई देते हुए प्रथम के उज्ज्वल करियर की कामना की है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि युवा पीढ़ी के लिए यह उपलब्धि प्रेरणादायक है और इससे शिक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश जाता है। शेट्टी परिवार ने सभी शुभचिंतकों और समर्थकों का आभार व्यक्त किया है।

'कुंआ खोदो, पानी पियो' आंदोलन से घिरे कार्यकारी अभियंता

जल संकट पर विभाग की कार्यशैली सवालों में...

महिलाओं का मैदान में उतरकर किया विरोध,संदीप पटनावर पर जानबूझकर देरी कराने के आरोप

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी में बढ़ते जल संकट के बीच अब वाटर सप्लाई विभाग के कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। अनियमित पानी सप्लाई और अधूरी योजनाओं से परेशान नागरिकों ने 'कुंआ खोदो, पानी पियो' आंदोलन शुरू कर दिया है, जिससे मनपा प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। जैतूनपुरा, बंगालपुरा, बर्फ गली, काप तालाब और कोटर गेट जैसे इलाकों की महिलाओं ने अब्दुल कलाम आजाद मैदान में कुदाल और गैता लेकर जमीन खोदते हुए विरोध दर्ज कराया।

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कई इलाकों में रात 2 बजे सिर्फ एक घंटे के लिए पानी सप्लाई की जा रही है, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। लोगों का कहना है कि मनपा प्रशासन घरपट्टी के नाम पर हर साल हजारों रुपये वसूलता है, लेकिन पिछले 20 वर्षों से पानी की स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाई है। जल संकट के लिए नागरिक सीधे तौर पर वाटर सप्लाई विभाग और उसके नेतृत्व को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

अब्दुल कलाम आजाद मैदान में पानी टंकी निर्माण की योजना बार-बार शुरू और बंद होने से भी लोगों में नाराजगी है। पहले योजना बनाई गई, फिर अचानक

कार्यकारी अभियंता (पानी पुरवठा) संदीप पटनावर

रद्द कर दी गई। स्थानीय मांग पर दोबारा काम शुरू हुआ और गड्ढे भी खोदे गए, लेकिन बिना स्पष्ट कारण बताए काम फिर रोक दिया गया। नागरिकों का आरोप है कि इस देरी के पीछे विभागीय स्तर पर समन्वय की कमी और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही है।

सामाजिक कार्यकर्ता जावेद किरन ने दावा किया कि हालिया नगरसेवक चुनाव के बाद कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक श्रेय लेने के लिए परियोजना रोकी गई और कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर जानबूझकर देरी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिससे आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इधर महिलाओं का जमीन खोदकर विरोध प्रदर्शन प्रशासन के लिए चेतावनी

माना जा रहा है। नागरिकों ने स्पष्ट किया है कि यदि जल संकट का स्थायी समाधान जल्द नहीं निकाला गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। अब निगाहें मनपा प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग पर टिकी हैं कि वे आरोपों का जवाब कैसे देते हैं और शहरवासियों को राहत दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं।

दीवार तोड़कर 23 लाख से ज्यादा की चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

सिटी जोन मोबाइल शोरूम में सेंधमारी का खुलासा,40 घंटे में पुलिस का बड़ा एक्शन

जले हुए सबूतों समेत लाखों का माल बरामद

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। शांतिनगर पुलिस ने मोबाइल शोरूम में हुई हाईप्रोफाइल सेंधमारी का महज 40 घंटे में पर्दाफाश कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोपालनगर स्थित 'सिटी जॉन' मोबाइल और एक्सेसरीज़ दुकान में 6 फरवरी की रात अज्ञात चोरों ने इमारत के पीछे की दीवार तोड़कर प्रवेश किया और महंगे मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत लाखों रुपये का सामान चोरी कर फरार हो गए थे। चोरी की कुल कीमत करीब 23 लाख 45 हजार 992 रुपये बताई गई थी।

घटना की सूचना मिलते ही शांतिनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने आजाद नगर शांतिनगर निवासी साहिद मोहम्मद उर्फ दंबग जफरूद्दीन अंसारी (20) और उजेर अहमद इस्लाहुर रहमान खान (23) को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने वारदात कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपियों के पास से विभिन्न कंपनियों के 108 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित कुल 16,77,407 रुपये का मुद्देमाल बरामद किया है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए करीब 6,68,587 रुपये कीमत के मोबाइल फोन, चार्जर और केबल आदि जलाने की कोशिश की थी, जिनके अवशेष भी पुलिस ने जब्त किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने आजाद नगर शांतिनगर निवासी साहिद मोहम्मद उर्फ दंबग जफरूद्दीन अंसारी (20) और उजेर अहमद इस्लाहुर रहमान खान (23) को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने वारदात कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपियों के पास से विभिन्न कंपनियों के 108 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित कुल 16,77,407 रुपये का मुद्देमाल बरामद किया है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए करीब 6,68,587 रुपये कीमत के मोबाइल फोन, चार्जर और केबल आदि जलाने की कोशिश की थी, जिनके अवशेष भी पुलिस ने जब्त किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त शशिकांत बोराटे (परिमंडल-2), सहायक पुलिस आयुक्त सचिन सांगले और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनायक गायकवाड के मार्गदर्शन में की गई। टीम में पुलिस निरीक्षक विनोद पाटिल, अतुल अडुरकर, सहायक पुलिस निरीक्षक योगेश गायकर, सहायक पुलिस उप निरीक्षक संतोष मोरे सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस के अनुसार मामले की आगे की जांच जारी है और चोरी में शामिल अन्य संभावित आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय चोरी के गिरोहों पर लगाम कसने की उम्मीद जताई जा रही है।

अजय राय ने सरकार पर बोला हमला : केंद्र ने मनरेगा को किया बर्बाद, मजदूरों पर हो रहा अत्याचार

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राजधानी लखनऊ में केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है, मजदूरों को समय पर मेहनताना नहीं मिल रहा और उन पर लगातार अत्याचार हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में जनता की आवाज उठाएगी।

अजय राय ने बताया कि 13 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में शहरों और गांवों में पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ होगी। यह पदयात्रा 75 जिलों में करीब 15 किलोमीटर की होगी, जिसमें मनरेगा मजदूरों समेत आम लोगों को जोड़ा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यूपी सरकार के बजट को जनविरोधी बताते हुए कहा कि 'यूपी के लोगों को इस बजट से कुछ भी नहीं मिला। सरकार बताए कि पिछले बजट का पैसा कहां खर्च हुआ। इस पर तुरंत श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के चलते लोग आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हैं।मथुरा में पूरे परिवार की आत्महत्या और वाराणसी में सुसाइड का जिक्र करते हुए अजय राय ने कहा कि इसके पीछे आर्थिक बदहाली बड़ी वजह है, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी है।

टी20 वर्ल्ड कप : सुपर ओवर थ्रिलर में दक्षिण अफ्रीका से हार पर राशिद खान ने जताई निराशा

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अहमदाबाद में खेला गया दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान मुकाबला रोमांच की नई मिसाल बन गया। दोनों टीमों के बीच यह मैच इतना कड़ा रहा कि नतीजा निकालने के लिए दो सुपर ओवर तक खेलने पड़े। आखिरकार दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में जीत दर्ज कर दो महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। हार के बाद अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टीम के प्रदर्शन पर गर्व जताया, लेकिन मौके गंवाने को हार की बड़ी वजह बताया।

हार के बाद अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और 190 से कम स्कोर पर विपक्ष को रोकना बड़ी उपलब्धि थी। राशिद ने माना कि पावरप्ले में विकेट गंवाना टीम के लिए नुकसानदायक रहा। उन्होंने कहा, लड़कों ने कमाल का काम किया, खासकर जिस तरह से उन्होंने बैट से शुरुआत की। उन्हें 190 के अंदर रोकना कमाल का

था। हारने वाली टीम का हिस्सा बनना बहुत अनलकी था। हमने मैदान पर अपना सब कुछ झोंक दिया। यह विकेट अच्छा है, आईपीएल में इस विकेट पर बहुत खेला है। टीम के साथ बातचीत हुई कि 'हां, उनकी शुरुआत अच्छी थी लेकिन आखिरी 10 ओवर में उन्हें रोकने की कोशिश करो'।'

राशिद ने कहा, 'कमाल की पारी, इसी के लिए वह मशहूर हैं। पावरप्ले के आखिरी कुछ ओवरों में जहां हमने जल्दी विकेट गंवाए, उसने उन्हें बैकफुट पर डाल दिया। कुल मिलाकर उन्होंने कमाल का खेला। हमारे पास मौके थे। आखिरी सुपर ओवर में भी, 1 बॉल पर 5 रन वैसे भी जा सकते थे। और समझदारी हो सकती थी। एक डाइव, एक बॉल से इसे खत्म किया जा सकता था। इस गेम को अगले राउंड में ले जाने के लिए पिछले डेढ़ साल से कड़ी मेहनत की है। बहुत निराशाजनक। जब भी आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह गर्व का पल होता है। मैं उन्हें जितना हो सके ऊपर रखने की पूरी कोशिश करूंगा।'

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 187 रन बनाए। मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी निभाते हुए टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया। अफगान गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाने की कोशिश की और विपक्षी टीम को 190 के अंदर रोकने में सफलता पाई। यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर था, लेकिन असंभव नहीं।

लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान ने आक्रामक शुरुआत की, लेकिन पावरप्ले के आखिरी ओवरों में जल्दी विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई। इसके बावजूद मध्यक्रम ने हिम्मत नहीं हारी और मैच को अंत तक खींचा। अफगान टीम 19.4 ओवर में 187 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। स्कोर बराबरी पर पहुंचने के बाद मुकाबला सुपर ओवर में गया, जिससे स्टेडियम में रोमांच चरम पर पहुंच गया।

टी20 विश्व कप : जीता हुआ मैच हार गया अफगानिस्तान दूसरे सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका ने मारी बाजी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के 13वें मैच में अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता हुआ मैच गंवा दिया। दरअसल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 188 रनों का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रन चाहिए थे, लेकिन मैच टाई हो गया। इसके बाद सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका ने ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच टाई कर दिया। फिर दूसरे सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका ने 23 रन बना दिए। जवाब में अफगानिस्तान 19 रन ही बना सका और एक रोमांचक मुकाबला हार गया।

इससे पहले यान रिकेल्टन और क्विंटन डीकॉक के अर्धशतकों और इन दोनों के बीच शतकीय साझेदारी की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद 6 विकेट पर 187 रन बनाए। रिकेल्टन ने 28 गेंद पर 61 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें

पांच चौके और चार छक्के शामिल हैं। क्विंटन डीकॉक ने 41 गेंद पर पांच चौकों और तीन छक्कों की मदद से 59 रन बनाए।

कप्तान एडन मार्क्रम (05) के जल्दी आउट होने के बाद इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी की। रिकेल्टन और डीकॉक के अलावा डेवाल्ड ब्रेविस ने 23, डेविड मिलर ने नाबाद 20 और मार्को यानसन ने 16 रन का योगदार दिया। अफगानिस्तान की तरफ से अजमतुल्लाह उमरजई सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 41 रन देकर तीन और कप्तान राशिद खान ने 28 रन देकर दो विकेट लिए। फजलहक फारुकी ने 32 रन देकर एक विकेट लिया। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने मार्क्रम का विकेट जल्दी गंवा दिया जिन्हें फारुकी ने एक बेहतरीन चेंज-अप गेंद से चकमा दिया। गेंद बल्लेबाज के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में उछल गई और मोहम्मद नबी ने मिड-ऑफ पर आसान कैच लपक लिया। डीकॉक ने चौथे ओवर में मुजीब उर रहमान की गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया और फिर अगली ही गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट में चौका जड़ा। रिकेल्टन ने भी उमरजई पर दो चौके लगाए। दक्षिण अफ्रीका ने पावरप्ले में एक विकेट पर 43 रन बनाए। इसके बाद डीकॉक और रिकेल्टन दोनों ने तेजी दिखाई तथा नबी और राशिद की स्पिन जोड़ी पर कुछ मनचाहे चौके और छक्के बटोरे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मैच में नहीं खेलने वाले स्पिनर नूर अहमद ने अपने पहले ओवर में 23 रन लुटा दिए।

भारत बनाम पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप

कोलंबो फ्लाइट का टिकट 1.45 लाख पार होटल का किराया भी आसमान पर पहुंचा

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। 15 फरवरी को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले ने क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। जैसे ही पाकिस्तान ने यह मैच खेलने की पुष्टि की, कोलंबो जाने वाली फ्लाइट्स और होटलों की मांग अचानक बढ़ गई। नतीजतन, नई दिल्ली और मुंबई से श्रीलंका की राजधानी तक की हवाई टिकटों के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। होटल रूम की कीमतों में भी तेज उछाल देखा जा रहा है। भारत बनाम पाकिस्तान मैच का असर अब ट्रैवल इंडस्ट्री पर साफ दिखाई दे रहा है।

भारत-पाकिस्तान मैच की आधिकारिक पुष्टि के बाद यात्रा बुकिंग में अचानक तेजी आई। ट्रैवल वेबसाइट्स पर 14 और 15 फरवरी के लिए दिल्ली और मुंबई से कोलंबो की फ्लाइट का किराया सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक दिख रहा है। जहां आमतौर पर कोलंबो के लिए सीधी उड़ान का किराया लगभग 30, 000 रुपए के आसपास रहता है, वहीं अब कुछ टिकटों की कीमत 1.45 लाख रुपए तक पहुंच गई है। खासकर मैच से एक दिन पहले और मैच के दिन की फ्लाइट्स सबसे महंगी हैं।

एयर इंडिया की नॉनस्टॉप उड़ानों के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली से कोलंबो के लिए किराया लगभग 90,

000 से 1.09 लाख रुपये के बीच पहुंच गया है। वहीं मुंबई से उड़ान भरने वाले यात्रियों को भी करीब 90, 000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। सिर्फ फ्लाइट ही नहीं, बल्कि कोलंबो में होटल के रेट भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गए हैं। तीन सितारा से लेकर पांच सितारा होटलों तक, एक रात ठहरने का किराया 1.14 लाख रुपए तक बताया जा रहा है। सामान्य दिनों में यही कमरे लगभग 40, 000 रुपए तक में उपलब्ध रहते हैं। लेकिन भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर भारी मांग के चलते प्रीमियम होटलों ने अपने रेट में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि बजट यात्रियों के लिए अभी भी विकल्प मौजूद हैं। छोटे होटल और गेस्ट हाउस में दो से तीन हजार रुपये प्रति रात के हिसाब से कमरे मिल सकते हैं, लेकिन इनकी उपलब्धता सीमित है।

फिन एलन ने रचा नया इतिहास अभिषेक का बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड ने यूएई को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। चेन्नई में खेले गए इस मुकाबले में कीवी टीम ने 174 रनों का लक्ष्य महज 15.2 ओवर में बिना विकेट गंवाए हासिल कर लिया। इस जीत के हीरो रहे ओपनर्स टिम सीफर्ट और फिन एलन, जिन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी से मैच एकतरफा बना दिया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 173 रन बनाए। कप्तान मुहम्मद वसीम (66) और अलीशान शराफू (55) ने दूसरे विकेट के लिए 107

रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी ने 2 विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत विस्फोटक रही। टिम सीफर्ट ने 42 गेंदों में नाबाद 89 रन बनाए, जबकि फिन एलन ने 50 गेंदों पर 84 रन ठोके। दोनों ने पहले विकेट के लिए अटूट साझेदारी कर टीम को रिकॉर्ड जीत दिलाई। इस पारी के साथ ही फिन एलन ने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन पूरे करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने यह मुकाम 2854 गेंदों में हासिल किया और भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2898 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी।

इसी बीच टीम इंडिया को झटका लगा है। अभिषेक शर्मा पेट में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती हैं और नामीबिया के खिलाफ मैच में उनके खेलने पर संशय बना हुआ है।

आरबीआई का बड़ा फैसला : शहरी सहकारी बैंकों से अब बिना गारंटी ऋण लेना होगा आसान!

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया। इसमें शहरी सहकारी बैंकों के लिए कुल परिसंपत्ति में असुरक्षित माने जाने वाले यानी बिना गारंटी वाले कर्ज का हिस्सा दोगुना कर 20 प्रतिशत तक करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण नियमों की समीक्षा के मसौदे के अनुसार, केंद्रीय बैंक व्यक्तिगत ऋण सीमा बढ़ाने और असुरक्षित ऋणों की परिको तर्कसंगत बनाने, इन ऋणों की व्यक्तिगत सीमा बढ़ाने और ऐसे कर्ज के लिए कुल सीमा को संशोधित करने का प्रस्ताव कर रहा है। आरबीआई ने कहा कि उसके दायरे में आने वाले वित्तीय संस्थान, संबंधित पक्ष और आम जनता चार मार्च, 2026 तक मसौदे पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि आरबीआई ने कुल परिसंपत्तियों में असुरक्षित कर्ज की सीमा को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा, "हालांकि इस सीमा से अधिक अतिरिक्त असुरक्षित ऋण केवल प्राथमिकता क्षेत्र के पात्र ऋणों के संबंध में ही स्वीकृत होंगे, जो प्रति उधारकर्ता 50, 000 रुपये की मौद्रिक सीमा पर निर्भर होगा।" इसके अलावा, उपभोक्ता टिकाऊ

वस्तुओं की खरीद के लिए सदस्यों को ऋण देने की सीमा को भी बढ़ाकर प्रति उधारकर्ता 2.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।

तीसरे और चौथे स्तर की शहरी सहकारी समितियों (यूसीबी) के लिए आवास ऋण की अवधि और स्थगन संबंधी आवश्यकताओं को विनियमन से मुक्त करने का प्रस्ताव है। आरबीआई ने इस महीने की मौद्रिक नीति समीक्षा में शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण मानदंडों की समीक्षा की घोषणा की थी। मौद्रिक नीति की घोषणा के दौरान, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था कि यूसीबी की प्रबंधन और तकनीकी क्षमता को मजबूत करने के लिए, केंद्रीय बैंक मिशन-सक्षम (सहकारी बैंक क्षमता निर्माण) शुरू करेगा। मल्होत्रा ने कहा, "इस मिशन का उद्देश्य यूसीबी से जुड़े 1.4 लाख से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करना है।

बेटे के करियर पर पत्नी सुनीता के आरोपों पर गोविंदा का पलटवार, कहा- 'परिवार के लिए छोड़ी राजनीति'

बॉलीवुड के 'चीची' यानी गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए चर्चा में रहते हैं। हाल ही में सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू में गोविंदा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने बेटे यशवर्धन के करियर को संवारने में कोई मदद नहीं की। अब गोविंदा ने इन आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपना पक्ष रखा है।

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपनी बात कहने से कभी नहीं कतरातीं, और हाल ही में वह तब सुर्खियों में आईं जब उन्होंने दावा किया कि गोविंदा ने कभी उनके बेटे यशवर्धन की मदद नहीं की या उसके करियर में मदद नहीं की। एक्टर ने अब अपनी पत्नी के आरोप पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, और कहा है कि उन्होंने अपने परिवार की खातिर पॉलिटिक्स छोड़ी क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी पॉलिटिकल लाइफ का उनके बच्चों पर बुरा असर पड़े। उन्होंने सुनीता के दावे को खारिज कर दिया, और बताया कि उन्होंने यशवर्धन के करियर को गाइड करने के लिए कदम उठाए थे। एएनआई से बातचीत में, गोविंदा से उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बेटे यशवर्धन के करियर में मदद न करने के बयान के बारे में पूछा गया। उन्होंने जवाब दिया, 'मैंने अपने परिवार के लिए पॉलिटिक्स छोड़ी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पॉलिटिकल लाइफ मेरी फैमिली लाइफ में रुकावट डाले और उन पर - खासकर मेरे बच्चों पर - बुरा असर डाले। इसलिए मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी।' उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने यशवर्धन को प्रोफेशनली गाइड करने के लिए कदम उठाए। गोविंदा ने कहा कि उन्होंने प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से बात की और उनसे यशवर्धन को गाइड करने के लिए कहा। गोविंदा ने कहा, 'मैंने नाडियाडवाला से कहा, तो उन्होंने यश को गाइड किया कि कैसे फिल्में बनाई जाती हैं, काम किया जाता है।'

आईसीसी रैंकिंग : अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती शीर्ष पर कायम, सिकंदर रजा बने नंबर 1 ऑलराउंडर

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। आईसीसी की ताजा टी20आई रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा बरकरार है। ओपनर अभिषेक शर्मा बल्लेबाजों की सूची में नंबर 1 स्थान पर बने हुए हैं, जबकि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज हैं। इस बीच जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने शानदार प्रदर्शन के दम पर टी20आई ऑलराउंडर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच जारी इन रैंकिंग्स ने क्रिकेट जगत में नई चर्चा छेड़ दी है।

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 909 रेटिंग अंकों के साथ टी20आई बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के फिल साल्ट (821), पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान (769), इंग्लैंड के जोस बटलर (766) और श्रीलंका के पथुम निसांका (754) को पीछे छोड़ रखा है। रैंकिंग में अन्य खिलाड़ियों ने भी छलांग लगाई है। न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट एक स्थान ऊपर चढ़कर आठवें पायदान पर पहुंच गए हैं।

श्रीलंका के कुसल मेंडिस ने छह स्थान की बढ़त लेकर 12वां स्थान हासिल किया। स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुनसे, भारत के ईशान किशन और नीदरलैंड्स के माइकल लेविट ने भी उल्लेखनीय सुधार किया है। टी20आई गेंदबाजों की रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती शीर्ष पर बने हुए हैं और पाकिस्तान के अबरार अहमद से मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। चक्रवर्ती की लगातार प्रभावी गेंदबाजी ने उन्हें नंबर 1 बनाए रखा है। श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा ने एक स्थान ऊपर चढ़कर पांचवां स्थान हासिल किया है और वह टॉप 10 में सबसे बड़ा बदलाव करने वाले गेंदबाज हैं। इसके अलावा, अर्शदीप सिंह (तीन स्थान ऊपर, 11वें), सलमान मिर्जा (नौ स्थान ऊपर, 13वें), ब्रैड इवांस (16 स्थान ऊपर, 15वें), मिशेल सेंटनर (चार स्थान ऊपर, 19वें) और ब्रैडली करी (25 स्थान ऊपर, 24वें) को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद टी20आई ऑलराउंडर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

सं. एसी/आरएस/एसआर/812/एमओएच/दिनांक-11.02.2026

अभिरुचि अभिव्यक्ति हेतु विज्ञापन

विषयः आर/दक्षिण प्रभाग के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में श्रेणी 'डी' के बहुउद्देशीय कर्मियों के रिक्त पदों को संविदा आधार पर भरने के संबंध में।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आर/दक्षिण प्रभाग की औषधालयों, कार्यालयों एवं श्मशानभूमि में श्रेणी 'डी' के रिक्त पदों को संविदा आधार पर भरने हेतु केवल वही संस्थाएं/कंपनियां आवेदन कर सकती हैं, जिन्हें बृहन्मुंबई महानगरपालिका के औषधालयों, बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यालय तथा बृहन्मुंबई महानगरपालिका श्मशानभूमि में संविदा आधार पर बहुउद्देशीय कर्मी उपलब्ध कराने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो। इच्छुक चैरिटेबल संस्थाएं/एकल स्वामित्व/साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, जो भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत हों (जिन संस्थाओं/कंपनियों की स्थापना का उद्देश्य अपने सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराना हो), उनसे आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर पात्रता सूची तैयार की जाएगी तथा लॉटरी पद्धति से चयन किया जाएगा।

आवेदन पत्र आर/दक्षिण प्रभाग के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग कार्यालय से 12/02/26 से 18/02/26 तक, समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक संस्थाएं/कंपनियां अधिक जानकारी, आवेदन पत्र तथा शपथपत्र (एफिडेविट) प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आर/दक्षिण प्रभाग के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग कार्यालय से संपर्क करें।

संस्थाओं/कंपनियों द्वारा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18/02/26, समय शाम 5:00 बजे तक है।

निर्धारित कार्यालय समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

पीआरओ/2958/विज्ञा./2025-26

चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य)
आर/दक्षिण प्रभाग

भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ स्वच्छ धोएं।

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी

बांधकाम विभाग, प्रभाग समिती क्रं.१

ई-निवीदा सुचना क्रमांक १८२ सन २०२५/२६ (तिसरा कॉल)

(महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान जिल्हास्तर योजने सन २०२५-२६ अंतर्गत)

भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागामार्फत खालील नमुद कामाचे निविदा फॉर्म दिनांक :- १२/०२/२०२६ ते दि.:- १७/०२/२०२६ पर्यंत विक्रीस उपलब्ध आहे.

अ.क्र.	कामाचे नांव	अंदाजपत्रकीय रक्कम	निविदापत्राची किंमत (रू.)
१	भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका हद्दीतील वॉर्ड क्रं. ११ ड मनपा स्कुल नं.६९ मनपा दवाखाना रेहमतपुर समिरच्या घरापासुन शाळेपर्यंत गटार बनविणे.	२४,९९,७०८/-	५९०/-
२	भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका हद्दीतील वॉर्ड क्रं. ११ ड दिनीयाद मस्जिद शौकत घर नं.९२४ ते मेमन किराणा स्टोर्स ते मनपा शौचालय पर्यंत गटार व पाथवेज बनविणे.	१४,९९,१९२/-	५९०/-
	वरील ऑनलाईन निविदा दि.१७/०२/२०२६ पर्यंत दुपारी ४.०० पर्यंत स्विकारण्यात येतील. तसेच सदरची निविदा ही दि.१८/०२/२०२६ रोजी संध्या. ४.०१ अथवा कार्यालयीन कामकाजाच्या सोई प्रमाणे निविदा समिती समक्ष उघडण्यात येईल. अधिक माहिती महानगरपालिकेच्या mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावरुन प्राप्त होऊ शकेल अथवा नविन शासकीय इमारतीमधील ५ व्या मजल्यावरील बांधकाम विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.		

XXX

(जमिल पटेल)
शहर अभियंता
भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका

जा.क्र./ज.सं.वि./११३
दि. ११/०२/२०२६

स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज में दसवां विश्व यूनानी दिवस ऐतिहासिक एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न

प्रयागराज। स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, प्रयागराज के अहमद हुसैन उस्मानी ऑडिटोरियम में दसवां यूनानी दिवस अत्यंत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस गरिमामय समारोह की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. वसीम अहमद ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जनाब महफूज़ुर्रहमान उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में प्रोफेसर जी.एस. तोमर, जनाब एम.एम. वारिस एवं पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अनवर अहमद कुरैशी, शामिल थे। अकादमिक इंचार्ज प्रोफेसर नजीब हंजला अम्मार और सामाजिक कार्यकर्ता शम्सुज़्ज़ुहा साहब भी समारोह में मौजूद रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ पवित्र कुरआन की तिलावत से हुआ, जिसके पश्चात सभी सम्मानित अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया गया। अतिथियों ने अपने संबोधन में यूनानी चिकित्सा पद्धति के महत्व, उसकी ऐतिहासिक सेवाओं तथा वर्तमान समय में उसके प्रचार-प्रसार पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर नजीब हंजला अम्मार ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कॉलेज का परिचय प्रस्तुत किया। प्रोफेसर कफील अहमद ने हकीम अजमल खान के जीवन और उनकी बहुआयामी सेवाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला।

प्राचार्य डॉ. वसीम अहमद ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में यूनानी चिकित्सा की उन्नति, शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि और जनसेवा के संकल्प को दोहराया तथा विद्यार्थियों को सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कॉलेज के सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके समर्पण एवं सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया।

पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अनवर अहमद कुरैशी ने अपने संबोधन में हकीम अजमल खान की महान सेवाओं की सराहना की और कॉलेज की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। प्रोफेसर जी.एस. तोमर ने यूनानी चिकित्सा की लोकप्रियता और जनसामान्य में बढ़ती रुचि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यूनानी दवाओं के लाभों को आधुनिक शोध के माध्यम से जनता तक पहुंचाना आवश्यक है। जनाब एम.एम. वारिस (ए डीआर एम) ने अपने विचारों में यूनानी चिकित्सा के विकास की सराहना की और विद्यार्थियों को यूनानी शिक्षा के बाद सिविल सेवा में जाने की सलाह दी, ताकि इस माध्यम से यूनानी चिकित्सा की बेहतर सेवा की जा सके।

मुख्य अतिथि (आई आर एस) जनाब महफूज़ुर्रहमान ने यूनानी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए यूनानी चिकित्सा से अपने भावनात्मक जुड़ाव का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उनके यहां यूनानी दवाएं बनाई जाती थीं और विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे यूनानी शिक्षा प्राप्त कर सिविल सेवा में प्रवेश करें, ताकि व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा पिछले सप्ताह से चल रही सांस्कृतिक एवं खेल प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेडल और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने यूनानी चिकित्सा पर आधारित कविताएं और ग़ज़लें प्रस्तुत कर श्रोताओं का मन मोह लिया तथा एक लघु फिल्म प्रदर्शन से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. फिरदौस अनीस ने कुशलतापूर्वक किया, जबकि डॉ. बिलाल अहमद ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए यूनानी दिवस के सफल आयोजन के लिए सभी प्रतिभागियों, आयोजकों और शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर निदेशक यूनानी सेवाएं, उत्तर प्रदेश प्रोफेसर डॉ. जमाल अख्तर ने भी कॉलेज प्रशासन और शिक्षकों को सफल आयोजन तथा प्रतियोगिता में सफल विद्यार्थियों को बधाई दी।

समारोह का समापन कॉलेज तराना और राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम में कॉलेज के सभी शिक्षकगण, विद्यार्थी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे और यूनानी दिवस को यादगार बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया।

इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन को मिली अंतरराष्ट्रीय मान्यता: डॉ. राकेश मिश्र

नई दिल्ली / लॉज़ेन । भारतीय मुक्केबाज़ी जगत के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है कि इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज़ी संघ की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई है। इस मान्यता के साथ भारतीय मुक्केबाज़ी को वैश्विक मंच पर नई पहचान और अवसर प्राप्त हुए हैं।

अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज़ी संघ के अध्यक्ष उमर क्रीमलेव ने फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. राकेश मिश्र को संबोधित संदेश में इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन की पारदर्शी कार्यप्रणाली, खेल के प्रति प्रतिबद्धता और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संचालन के कारण यह मान्यता प्रदान की गई है। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि आईएबीएफ की सक्रिय भागीदारी से वैश्विक स्तर पर मुक्केबाज़ी खेल के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी।

इस सदस्यता के साथ भारतीय एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और आयोजनों में भागीदारी का औपचारिक आमंत्रण मिला है। इससे भारतीय मुक्केबाज़ों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव, उन्नत प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा तथा वैश्विक मुक्केबाज़ी समुदाय और अधिक सशक्त बनेगा।

डॉ. राकेश मिश्र ने इस अवसर पर कहा कि यह उपलब्धि भारतीय बॉक्सिंग के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज़ी संघ के निदेशक मंडल और सदस्य देशों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मान्यता भारतीय मुक्केबाज़ों को ओलंपिक स्तर तक अधिक अवसर दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि फेडरेशन अब जमीनी स्तर से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ताकि भविष्य में सक्षम और प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी तैयार किए जा सकें।

फेडरेशन के महासचिव राकेश ठाकरान ने इस उपलब्धि पर देशभर की राज्य स्तरीय बॉक्सिंग संघों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों, कोचों, रेफरियों और तकनीकी अधिकारियों से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर भारतीय मुक्केबाज़ी के इस नए दौर में सक्रिय योगदान दें।

कुल मिलाकर, अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलने से भारतीय मुक्केबाज़ी के लिए वैश्विक मंच पर नए अवसर खुलेंगे और देश के उभरते खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की मजबूत आधारशिला मिलेगी।

मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को पुलिस ने जागरूक

सिद्धार्थनगर। जिले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओ की सुरक्षा में चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज बृजेश कुमार वर्मा तथा थानाध्यक्ष चंद्रकांत पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना त्रिलोकपुर मिशन शक्ति टीम उप निरीक्षक तालिमुद्दीन खान, कांस्टेबल सत्यप्रकाश यादव, कांस्टेबल जुनेद अहमद, महिला कांस्टेबल प्रीती द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा चिताही में महिलाओं/ बालिकाओं को महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा व उससे बचाव के संबंध मे जागरुक किया गया तथा नये कानून व विभिन्न हेल्पलाइन नम्बर आदि के बारें पम्पलेट वितरित कर जागरुक किया गया व विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे मे जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व बहू सम्मेलन अभियान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना रानी लक्ष्मी बाई बाल एवं महिला सम्मान कोष नारी शक्ति वंदन अधिनियम मातृ शक्ति को सम्बल निराश्रित महिला पेंशन योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आदि अन्य योजनाओ से संबंधी जानकारी को बताया गया व जागरूक किया गया

मिशन शक्ति फेज 5.0 कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण, एंटी रोमियो अभियान एवं साइबर अपराध सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी देते हुए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर- 112, पुलिस आपातकालीन सेवा 1090, वूमेन पावर हेल्पलाइन 1076, माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 108, एंबुलेंस सेवा 1930, साइबर अपराध हेल्पलाइन 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन 102, स्वास्थ्य सेवा 181 वीमेन हेल्पलाइन 101अग्निशमन सेवा के बारे में जानकारी दी गई ।

गठबंधन रहेगा, लेकिन मंत्री पद नहीं: तमिलनाडु में कांग्रेस के लिए एमके स्टालिन की 'रेड लाइन'

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाए रखने की पुष्टि की है, लेकिन सरकार में सत्ता-साझेदारी की किसी भी संभावना को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। उन्होंने मंत्री पद की मांगों को 'सोची-समझी साजिश' बताते हुए कहा कि डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में शासन में हिस्सेदारी का कोई नियम तमिलनाडु में लागू नहीं होता।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि हाल के दिनों में कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा डीएमके सरकार में मंत्री पद की मांग उठाई गई थी, लेकिन साझा शासन मॉडल तमिलनाडु के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्ता-साझाकरण की यह अवधारणा राज्य की राजनीतिक परंपराओं से मेल नहीं खाती।

उन्होंने दोहराया कि चुनावों में कांग्रेस डीएमके गठबंधन का हिस्सा बनी रहेगी।

स्टालिन ने यह भी कहा कि गठबंधन को कमजोर करने के उद्देश्य से इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि डीएमके-कांग्रेस गठबंधन सौहार्दपूर्ण है और मीडिया द्वारा अनावश्यक अटकलें लगाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि राहुल गांधी उनके लिए भाई जैसे हैं और उनका रिश्ता राजनीति से परे है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने डीएमके नेता कनिमोझी से बातचीत कर गठबंधन में किसी भी संभावित तनाव को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है।

इससे पहले तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेल्वा पेरुंथगई ने भी संकेत दिया था कि डीएमके-कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह तय है और औपचारिक सीट बंटवारे पर बातचीत शीघ्र शुरू होगी। उन्होंने कहा कि डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन मजबूत है और जनता पहले ही इस सरकार पर भरोसा जता चुकी है।

पूर्व उच्चायुक्त का दावा : बांग्लादेश-अमेरिका डील से भारत को खतरा नहीं, अपने ही जाल में फंसेगा ढाका

ढाका **(एजेंसी)**। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुए रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत में किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। यह कहना है बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त वीणा सिकरी का। वीणा सिकरी ने कहा कि भारत को इस समझौते से घबराने की कोई वजह नहीं है और इसके पीछे दो अहम कारण हैं। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में बांग्लादेश को अमेरिकी बाज़ार में जीरो टैरिफ मिलने की संभावना है, वे मुख्य रूप से मैन-मेड यार्न, कॉटन यार्न और कपास से जुड़े हैं। 'इन सभी उत्पादों की सप्लाई भारत पहले से ही बेहद प्रतिस्पर्धी दामों पर और बहुत तेज़ डिलीवरी के साथ करता रहा है। सिकरी ने कहा बांग्लादेशी निर्यातक भारत से एक हफ्ते के भीतर ये कच्चा माल हासिल कर सकते हैं । वीणा सिकरी ने बांग्लादेश द्वारा बोइंग विमानों की खरीद पर भी सवाल उठाया। 'बांग्लादेश बोइंग के इतने बड़े जेट खरीदने की बात कर रहा है, लेकिन भुगतान कौन करेगा? इसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज़ लेना पड़ेगा। इससे उनकी अर्थव्यवस्था और कमज़ोर होगी, ' उन्होंने कहा। गौरतलब है कि अमेरिका और बांग्लादेश ने सोमवार को संयुक्त राज्य अमेरिका-बांग्लादेश पारस्परिक व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और बांग्लादेश के वाणिज्य, वस्त्र, जूट एवं नागरिक उड्डयन सलाहकार शेख बशीर उद्दीन ने हस्ताक्षर किए।

ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला!

नेतन्याहू कड़ी सुरक्षा के साथ एमरजैंसी पहुंचे अमेरिका, खतरनाक एजेंडे पर ट्रंप से 7वीं मुलाकात

यरुशलम **(एजेंसी)**। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार रात वॉशिंगटन पहुंचे वह भी उस स्तर की सुरक्षा के साथ, जैसी आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति को दी जाती है। आज उनकी मुलाकात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होनी है और कूटनीतिक हलकों में इसे बेहद संवेदनशील और खतरनाक मोड़ माना जा रहा है।यह दौरा पहले अगले हफ्ते तय था, लेकिन नेतन्याहू ने इसे जल्द कराने पर ज़ोर दिया, जब ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने ओमान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से बातचीत की। उस बातचीत में दोनों पक्षों ने माना कि चर्चा सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम तक सीमित है यही बात नेतन्याहू को नागवार गुज़री।

नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका-ईरान बातचीत में सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दा नहीं, बल्कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक, मिडिल ईस्ट में ईरान समर्थित मिलिशियाओं (हिज़्बुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद, हूती) को समर्थन खत्म करने की शर्त, और तेहरान पर कड़े अल्टीमेटम लगाए जाएं।यानी साफ शब्दों में ईरान को बातचीत नहीं, आत्मसमर्पण पर मजबूर किया जाए।

यह बीते 12 महीनों में ट्रंप और नेतन्याहू की 7वीं आमने-सामने मुलाकात है जो किसी भी वैश्विक नेता से कहीं ज्यादा। नेतन्याहू इसे 'अभूतपूर्व रिश्ता' बताते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर वह प्रधानमंत्री न होते, तो 'शायद आज इजरायल अस्तित्व में ही न होता।' राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, नेतन्याहू ट्रंप के साथ अपनी निजी केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर विटकॉफ और कुशनर की अपेक्षाकृत नरम नीति को कमजोर करना चाहते हैं।

ईरान ने भी इस दबाव को भांप लिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारीजानी ने अमेरिका को चेताया कि वह नेतन्याहू को बातचीत की शर्तें तय न करने दे।उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका को 'ज़ायोनिस्ट ताकतों की विनाशकारी भूमिका' से सतर्क रहना चाहिए।

पहले दौर की बातचीत में एक असाधारण कदम उठाया गया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेनाओं के कमांडर जनरल ब्रैड कूपर खुद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। यह सीधा संदेश था कि बातचीत असफल हुई तो सैन्य विकल्प तैयार हैं। अमेरिका पहले ही क्षेत्र में एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और उसके एस्कॉर्ट युद्धपोत तैनात कर चुका है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर बातचीत नाकाम रही, तो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेजा जा सकता है।

ऑपरेशन सिंदूर का 'हीरो' था राफेल, पाकिस्तान में मचाई थी तबाही

नई दिल्ली। वायु सेना के उप प्रमुख एयर मार्शल नागेश कपूर ने बुधवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल लड़ाकू विमान हीरो थे और भारतीय वायु सेना का लक्ष्य और अधिक बहु-भूमिका लड़ाकू विमान (एमआरएफए) शामिल करना है। वायु शक्ति 2026 अभ्यास के अनावरण समारोह में एक सभा को संबोधित करते हुए एयर मार्शल नागेश कपूर ने कहा कि आतंकवाद के हर कृत्य का करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जैसलमेर में वायु शक्ति अभ्यास के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की झलकियाँ जनता को दिखाई जाएंगी।

वायु सेना के उप प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल निस्संदेह हीरो था। भारतीय वायु सेना और अधिक एमआरएफए शामिल करने की योजना बना रही है, जो राफेल या कोई अन्य विमान हो सकता है, जिन पर विचार-विमर्श चल रहा है और अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से यह स्पष्ट संदेश मिला कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी धरती पर किए गए हर आतंकी कृत्य का जवाब दिया जाएगा और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वायु शक्ति 2026 अभ्यास के दौरान आपको ऑपरेशन सिंदूर के सटीक निशानेबाजी के कुछ उदाहरण देखने को मिलेंगे। हमारा काम प्रदर्शन करना है। इस प्रदर्शन को देखने वालों पर निर्भर करता है कि वे इससे क्या संदेश लेना चाहते हैं।

पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई, 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। भारत की सटीक हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक संघर्ष चला। इन हमलों में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) में स्थित नौ प्रमुख आतंकी लॉन्चपैड नष्ट कर दिए गए थे। इन हमलों में लश्कर-ए-तैबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाया गया था और 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे।

रूसी ड्रोन हमले में पूरा यूक्रेनी परिवार तबाह

तीन मासूमों व पिता की गई जान जिंदगी-मौत की जंग लड़ रही गर्भवती मां

कीव **(एजेंसी)**। यूक्रेन के उत्तर-पूर्वी खारकीव क्षेत्र में रूस द्वारा किए गए एक भीषण ड्रोन हमले ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, रात के समय एक रूसी ड्रोन ने बोहोदुखिव कस्बे में एक रिहायशी मकान को निशाना बनाया, जिसमें एक पिता और उसके तीन छोटे बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। खारकीव क्षेत्रीय अभियोजक कार्यालय ने बताया कि हमले में मकान पूरी तरह नष्ट हो गया और आग लग गई, जिससे परिवार के सभी सदस्य मलबे के नीचे दब गए। मृतकों में 34 वर्षीय पिता, दो साल के जुड़वां बेटे और उनकी एक साल की बेटी शामिल हैं।

मलबे से जीवित निकाली गई मां की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वह 35 सप्ताह की गर्भवती हैं और उन्हें विस्फोट के कारण गंभीर चोटें, दिमागी आघात, जलने के घाव और सुनने की क्षमता में नुकसान हुआ है। यूक्रेनी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह हमला गेरान-2 ड्रोन से किया गया, जो ईरानी शाहिद ड्रोन का रूसी संस्करण माना जाता है। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार, रूस ने बीती रात यूक्रेन पर कुल 129 लंबी दूरी के ड्रोन दागे। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस-यूक्रेन युद्ध लगभग चार साल पूरे करने वाला है और अमेरिका के नेतृत्व में शांति प्रयास जारी हैं।

इधर, जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनी ड्रोन हमले से रूस के वोल्गोग्राद शहर में एक औद्योगिक संयंत्र में आग लग गई। वोल्गोग्राद क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई बोचारोव ने बताया कि ड्रोन के टुकड़ों से एक अपार्टमेंट इमारत को भी नुकसान पहुंचा है।

पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान

अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ टॉयलेट पेपर से भी बदतर व्यवहार किया

इस्लामाबाद **(एजेंसी)**। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपनी ही सरकार की पुरानी नीतियों और अमेरिका के साथ संबंधों पर कड़ा प्रहार किया है। संसद में एक बहस के दौरान उन्होंने बेबाक अंदाज में कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ 'टॉयलेट पेपर से भी बदतर' व्यवहार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान को केवल एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया और फिर कचरे की तरह फेंक दिया गया।

आसिफ ने पाकिस्तान के विवादित अतीत और आतंकवाद के साथ उसके जुड़ाव को सैन्य तानाशाहों की गलती बताया। उन्होंने पूर्व सैन्य शासकों-जनरल जिया-उल-हक और जनरल परवेज मुशर्रफ-का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने इस्लाम के नाम पर नहीं, बल्कि एक महाशक्ति (अमेरिका) को खुश करने के लिए पाकिस्तान को अफगान युद्ध की आग में झोंका। रक्षा मंत्री ने एक बड़ा कबूलनामा करते हुए कहा कि अफगान संघर्षों में पाकिस्तान की भागीदारी धार्मिक कर्तव्य नहीं थी। उन्होंने माना कि हजारों पाकिस्तानियों को 'जिहाद' के बैनर तले लड़ने के लिए लामबंद किया गया था, जो कि पूरी तरह भ्रामक और देश की स्थिरता के लिए घातक साबित हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि इस नैरेटिव को सही ठहराने के लिए देश की शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किए गए, जिसके परिणाम आज भी समाज भुगत रहा है। ख्वाजा आसिफ ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान आज जिस आतंकवाद और कट्टरपंथ का सामना कर रहा है, वह पिछले तानाशाहों द्वारा लिए गए गलत फैसलों का 'ब्लोबैक' (दुष्प्रभाव) है।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)